खबर पेज 8 पर

गंभीर समाचार

समय-समाज-संस्कृति

खबर पेज 7 पर

वर्ष -12 | अंक-30 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, सोमवार 1 - 15 जून 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ - 8

सुविचार

- ''जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ।''
- ''समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सिखाता है।''

शेरो-शायरी

- चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुझे सारी उम्र... बस तू कभी जिसे भूल न पाए वो चाहत यक़ीनन हमारी होगी।
- हालात कह रहे हैं हम मिल ना सकेंगे कभी, उम्मीद कह रही है, बस थोड़ा और इंतजार कर।
- हमने सोचा था जिंदगी बदल देंगे, पर वो बदल गए... और जिंदगी वही रह गई...
- खुश रहो, मस्ती करो और जिंदगी जी लो, हर दिन को हंसी के रंग में रंगीन कर लो।

अमेरिका-ईरान के बीच समझौते का मोदी ने किया स्वागत

निज संवाददाता : अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के साथ उम्मीद है कि इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही आवाजाही, व्यापार की स्वतंत्रता फिर से बहाल होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चनें खड़ी हुईं और कई देशों को जानमाल का नुकसान हुआ। उन्होंने बातचीत से स्थायी समझौते की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा-मैं पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं।

जुलाई में टीएमसी के बागी सांसद कर सकते हैं 'बड़ा खेला'?

'निज संवाददाता : बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह बिखरने के कगार पर है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्तों की तरह भरभरा रही है। इसी क्रम में तृणमूल के बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय करने का फैसला किया है। उनका यह प्लान सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। उनका मकसद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर कब्जा करना है, ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मामले में हुआ था। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कभी करीबी रहे सुदीप बंदोपाध्याय ने यह बात साफ की है। यह बताते हुए कि इस गुट के पास पार्टी के 28 में से दो-तिहाई सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में यही तरीका अपनाया जाता है।उन्होंने कहा कि हालांकि दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए संख्या बल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके आधार पर तुरंत पार्टी का नाम नहीं मांगा जा सकता।

सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि जब आप पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों के साथ अलग होते हैं, तो आप पहले ही दिन उस पार्टी का नाम नहीं मांग सकते... जुलाई में हम तृणमूल (नाम) हमें सौंपने की मांग करेंगे क्योंकि हमारे पास तृणमूल का दो-तिहाई बहुमत है। फिर अदालत इस पर फैसला करेगी।गौरतलब है कि तृणमूल के बागी विधायकों ने काफी पहले ही दावा किया था कि वे ही असली तृणमूल हैं। एकनाथ शिंदे के उलट- जिन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा किया था। इन बागियों ने इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि बागी गुट कई तरह के तर्क देते हुए खुद को असली तृणमूल बताने का दावा करेगा।सूत्रों का कहना है कि तृणमूल अपने ही संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हुए कई फैसले लिए गए हैं।

इसमें इस बात की जानकारी होगी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मनमाने ढंग से फैसले कैसे ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल के बंटवारे की प्रक्रिया वही होगी जो शिवसेना, एनसीपी और एलपीजी के मामलों में अपनाई गई थी। हालांकि, अलग गुट बनाना या यह दावा करना कि बागी गुट ही असली टीएमसी है, मामला अंततः कोर्ट में ही जाता है।असली पार्टी वाले फॉर्मूले के लिए विलय की जरूरत नहीं होती। लेकिन तृणमूल के मामले में, संसद के मॉनसून सत्र से पहले कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए विलय का फैसला लिया गया। बागी नेताओं की स्पीकर से मुलाकात से ठीक पहले, तृणमूल के कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने ओम बिरला से मुलाकात की और अभिषेक बनर्जी का पत्र सौंपा। इस पत्र में मांग की गई थी कि वे अलग गुट बनाने की बागियों की मांग को खारिज कर दें।

इसमें सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया गया था जिनमें लेजिस्लेचर पार्टी (विधायक दल) के मुकाबले पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी गई थी।यह कहना मुश्किल है कि विलय के बाद, तृणमूल के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर कोर्ट में क्या रुख अपनाया जाएगा। शिवसेना के बंटवारे का मामला, जिसमें चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने हाल ही में जल्द फैसले की उम्मीद में सुनवाई की मांग की है।

अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त करने के लिए नए वित्त मंत्री ने बनाया 'मार्शल प्लान'

15 सालों में बंगाल की वित्तीय संरचना हो गई कमजोर

निज संवाददाता : भारी कर्ज, रेवेन्यू घाटा, ज़ीरो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कोई नौकरी नहीं। इन सबके चलते पिछले 15 सालों में बंगाल की वित्तीय संरचना लगातार कमजोर होती गई है। उस स्थिति से इकॉनमी को उबारना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी की अगुआई वाली शुभेंदु अधिकारी सरकार के दौरान वित्त विभाग की जिम्मेदारी काबिल मंत्री स्वपन दासगुप्ता को मिली। चार्ज संभालते हुए उन्होंने इकॉनमी को उबारने के लिए यूरोपियन स्टाइल में मार्शल प्लान की बात की। उनके मुताबिक, कई रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स के जरिए राज्य के वित्तीय संरचना को ठीक करके एक अच्छी स्थिति में लाना मुमकिन है। मार्शल प्लान के मुताबिक काम कैसे आगे बढ़ेगा? मार्शल प्लान क्या है? यह यूरोपियन देशों में इकॉनमिक रिवाइवल में कैसे असरदार हुआ?

आइए पहले इस प्रसंग को जानते हैं। उस समय के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी. मार्शल ने दूसरे विश्व युध्द से तबाह हुए यूरोप के एक के बाद एक देशों को फिर से बनाने के लिए एक खास प्लान अपनाया था। उनका मानना था कि कोई भी देश तब तक उबर नहीं सकता जब तक वह इकॉनमिक रूप से आत्मनिर्भर न हो। इसलिए, मार्शल ने युद्ध से जूझ रहे देशों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद का ऐलान किया। लोन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कई तरह की मदद दी गई। इसके आधार पर, दो दशकों के अंदर वेस्ट जर्मनी समेत कई यूरोपियन देशों की फाइनेंशियल रीढ़ मजबूत हुई। प्रोडक्शन बढ़ाना, रोज़गार बढ़ाना और औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र को मजबूत करना आज भी इतिहास के सबसे चर्चित टॉपिक में से एक है। वे नुकसान को जल्दी ठीक करने में माहिर हैं। राज्य के नए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के मुताबिक, ऐसा मार्शल प्लान ही बर्बाद हुई इकॉनमी को फिर से खड़ा कर सकता है। हालांकि, स्वपन खुद सोचते हैं कि यह बंगाल के लिए एक बड़ी चुनौती है। वह प्लान कैसे काम करेगा? वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन, निवेश और सरकारी मदद - इन सभी को मिलाकर एक आदर्श प्लान बनाना होगा। उन्हें उम्मीद है कि राज्य में डबल इंजन सरकार फिलहाल उस प्लान को लागू करने में बहुत मदद करेगी। केंद्र की वित्तीय मदद, अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद और सबसे बढ़कर, केंद्र के कई विकास परियोजना इस मार्शल प्लान में शामिल होने वाले हैं। इस बारे में स्वप्न दासगुप्ता ने जीरामजी प्रोजेक्ट यानी 100 दिन काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। वित्त मंत्री का मानना है कि अगर इसे बंगाल में सभी स्तर पर लागू किया जाए, तो शुरुआत में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। क्योंकि, इससे रोजगार बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। वहीं, नए वित्त मंत्री निजी निवेश क्षेत्र से मदद लेने के पक्ष में हैं। उनके मुताबिक, जो इंस्टीट्यूशन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे का विकास के लिए लोन देने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें समर्थन किया जाना चाहिए। हालांकि, सबसे ज़रूरी बात नाजुक वित्तीय संरचना को मजबूत करना है। फिलहाल, बंगाल कई तरह की फाइनेंशियल जिम्मेदारियां उठा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू किए गए कई अलाउंस हैं। इसके अलावा, कर्ज का भारी बोझ भी है। हालांकि बंगाल पर भारी कर्ज कोई नई बात नहीं है। यह उस लेफ्ट (वाममोर्चा शासन) पीरियड से चला आ रहा है। वित्त मंत्री पंजाब और केरल की तरह राज्य की जीडीपी ग्रोथ को इस कर्ज को चुकाने का एक तरीका मानते हैं।

स्वपन दासगुप्ता के 'मार्शल प्लान' के तीन फेज़

1. खर्च के मुकाबले राजस्व संग्रह बढ़ाना। 90 परसेंट खर्च सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और लोगों को मिलने वाली सब्सिडी पर होता है। इसके अलावा, लक्ष्मी भंडार जैसे कई सोशल प्रोजेक्ट्स पर भी काफी खर्च हुआ है। अब हमें उनके बारे में नए सिरे से सोचना होगा।
2. ब्याज दर पर लगाम लगाना। राज्य पर अभी करीब 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके ब्याज पर 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं, जो कुल रेवेन्यू का 42 फीसदी है। इस समस्या को जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है।
3. निवेश दर को और बढ़ाना। हालांकि कई प्राइवेट कंपनियां पहले से ही राज्य में अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन इसे लंबे समय तक जारी रखकर राज्य की आर्थिक गति को बढ़ाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। वित्त मंत्री उस काम के जरिए इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि स्वपन दासगुप्ता का मार्शल प्लान, उसकी पॉलिसी बनाना, उसे लागू करना और राज्य सरकार की पॉलिटिक्स- ये सब एक ही रास्ते पर चलेंगे या नहीं। यानी, क्या बंगाल में आर्थिक सूखा सच में दूर होगा और खुशहाली लौटेगी?

सियासत की दुनिया में सस्ती चीज में बदलती वफादारी

संजय सक्सेना

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जहां वफादारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, वहीं क्या सियासत की दुनिया में वफादारी सबसे सस्ती चीज होती है? आज यह सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है। क्या जब तक सत्ता का 'सूरज' चमकता रहता है, दरबार में भीड़ लगी रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज 'अस्ताचल' होने लगता है, सियासी 'महफिल' में सन्नाटा छा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ठीक यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद तृणमूल कांग्रेस की बगावत ने पार्टी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। दिल्ली से कोलकाता तक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मनमानी के खिलाफ पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों और 58 से अधिक विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वैसे यह महज एक पार्टी का संकट नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के उस गहरे घाव को उजागर करता है, जिसे मौकापरस्ती का नासूर कहते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने 45.43 प्रतिशत वोट पाकर सत्ता पर कब्जा किया और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 7.16 प्रतिशत गिर गया। विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम में ममता बनर्जी की पार्टी को मात्र 80 सीटें मिलीं। ममता बनर्जी के 35 में से 22 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, यानी करीब 63 प्रतिशत मंत्री चुनाव हार गए। खुद ममता बनर्जी भी अपने पुराने गढ़ भवानीपुर में हार गईं। पंद्रह साल की सत्ता का यह अंत था, लेकिन असली तमाशा इसके बाद शुरू हुआ।पिछले 14 दिन में ही पांच बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अपनी राज्यसभा सीट भी छोड़ दी है। जिस सुखेंदु शेखर राय को ममता का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, उन्होंने जाते-जाते भाजपा की तारीफ में पत्र लिखा। 14 बागी सांसद भाजपा के राष्ट्रीय रणनीतिकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर लंच के लिए जुटे, जहां पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। यह लंच महज खाने का नहीं, सियासी पाला बदलने का आयोजन था। बागियों की फेहरिस्त लंबी है। काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा समेत 19 सांसदों के नाम बागी सूची में हैं। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने खुलकर कहा कि भारी भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी की हार हुई है। उन्होंने संकेत दिए कि वे एनडीए का समर्थन करेंगी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करेंगी। टीएमसी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दी।लेकिन यह बीमारी सिर्फ तृणमूल की नहीं है। भारतीय राजनीति का पूरा इतिहास ऐसे मौकापरस्तों से भरा पड़ा है, जिन्होंने सत्ता के लिए अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को ताक पर रख दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, तब से कांग्रेस का एक के बाद एक बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ता चला गया।

तृणमूल कांग्रेस का विघटन

गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हेमंत बिस्वा सरमा, जगदंबिका पाल, अदिति सिंह काफी लंबी लिस्ट है। राहुल-प्रियंका के सबसे करीबी आरपीएन सिंह तक ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ये वो लोग थे, जो कभी गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ही पलट दी और सीधे केंद्र में मंत्री बन गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई तक की बात की थी, वे भी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर बाद में भाजपा की गोद में जा बैठे। नारायण राणे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी यही रास्ता चुना। एक नेता ने जाते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 55 साल के साथ को छोड़कर पार्टी बदल लेंगे, लेकिन देश के लिए मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। पचपन साल की निष्ठा रातोंरात इस तरह बदल जाती है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इन सबके बीच एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इन नेताओं में से कोई एक भी वैचारिक आधार पर पार्टी बदलता है? जवाब ज्यादातर नकारात्मक ही है। टिकट न मिलना, पद से हटाया जाना, या सत्ता की धूप से दूर हो जाना, यही तीन कारण होते हैं, जो नेताओं को रातोंरात क्रांतिकारी बना देते हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, तो उन्होंने पार्टी ही बदल दी। जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में तवज्जो नहीं मिली, तो उन्होंने भाजपा में शरण ली। यह बात और है कि भाजपा ने भी इन्हें उचित महत्व देने में कोई कमी नहीं रखी। तृणमूल के संदर्भ में यह और भी विडंबनापूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी की पहचान हमेशा से एक फाइटर नेता की रही है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अकेले दम पर तृणमूल कांग्रेस बनाई और 2011 में 34 साल पुराने वामपंथ को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन आज उनकी खुद की बनाई पार्टी में वही हो रहा है, जो उन्होंने कांग्रेस में महसूस करके पार्टी छोड़ी थी। यह राजनीतिक न्याय का एक कड़वा चक्र है। भारतीय राजनीति में दल-बदल को रोकने के लिए दसवीं अनुसूची यानी एंटी-डिफेक्शन लॉ बना, लेकिन नेताओं ने उसकी भी काट निकाल ली। दो-तिहाई का फॉर्मूला हो या व्यक्तिगत इस्तीफे का रास्ता, जहां कानून की दीवार खड़ी होती है, सियासतदान वहां सुरंग खोद लेते हैं। तृणमूल के बागियों ने भी यही किया। व्यक्तिगत इस्तीफे देकर या अलग गुट बनाकर वे उस कानूनी जाल से बाहर निकलने की कोशिश में हैं, जो उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है। असल सवाल यह नहीं है कि ममता के साथी उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं या कांग्रेस के दिग्गज भाजपा में क्यों जा रहे हैं।

असल सवाल यह है कि भारतीय मतदाता कब तक इस तरह के नेताओं को माफ करता रहेगा? जो नेता आज एक पार्टी की विचारधारा को गाली देकर दूसरी पार्टी में जाता है, वह अगले चुनाव में फिर टिकट मांगता है और अक्सर मिल भी जाता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। पश्चिम बंगाल की ताजा सियासत एक आईना है, जिसमें पूरे भारत की राजनीति का चेहरा दिखता है। सत्ता जब तक रहती है, वफादारी की कसमें खाई जाती हैं। सत्ता जाते ही वफादारी के ये धागे खुद-ब-खुद टूट जाते हैं। ममता बनर्जी ने जो बोया था, वह काटने का वक्त आ गया। लेकिन इस फसल से सीख सिर्फ ममता के लिए नहीं, हर उस दल के लिए है, जो अपने नेताओं को विचारधारा की बजाय सत्ता के लालच पर टिकाए रखता है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि संगठन की जड़ें सत्ता की जमीन में नहीं, जनता के विश्वास में होती हैं। जिस दिन यह जड़ें मजबूत होंगी, उस दिन मौकापरस्तों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

लंबी मूंछ नहीं रख पाएंगे सेना के जवान

महिला सैनिक नहीं लगा पाएंगी लिपिस्टिक

निज संवाददाता : भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल और गुलामी के दौर की पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग (रहन-सहन) नियमों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब सैनिकों की मूंछों का आकार 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्दी में रहते हुए डियोड्रेंट या परफ्यूम लगाने पर पाबंदी होगी, हालांकि आफ्टर-शेव लोशन का उपयोग किया जा सकता है। महिला सैन्य अधिकारियों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन पहनने पर सख्त रोक लगाई गई है। महिला कर्मी सिंदूर लगा सकती हैं, बशर्ते वह बेरेट या पीक कैप पहनने के बाद बाहर से दिखाई न दे।नए मैनुअल में सैनिकों के रहन-सहन और ग्रूमिंग के मानकों को भी कड़ाई से परिभाषित किया गया है। शरीर पर टैटू बनवाने, बॉडी पियर्सिंग और वर्दी में किसी भी प्रकार का ब्रेसलेट पहनने पर पूरी तरह से

प्रतिबंध रहेगा। केवल पूजा के दिन कलाई पर कलावा बांधने की छूट होगी। सिख सैनिकों को छोड़कर किसी भी अन्य सैनिक को धार्मिक चिह्न प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। चमकीली पाउच बेल्ट को मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से हटा दिया गया है। ये ड्रेस राष्ट्रपति भवन, राजभवन के राजकीय कार्यक्रमों या प्रधानमंत्री और सेना कमांडरों के आवासों पर आयोजित होने वाले औपचारिक भोज के दौरान पहनी जाती हैं। हालांकि, बख्तरबंद कोर, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, आर्टिलरी रेजिमेंट, राइफल रेजिमेंट और सिग्नल्स कोर के कर्नल रैंक तक के अधिकारी अभी भी रेजिमेंटल कार्यक्रमों में इसे पहन सकेंगे।फॉर्मल कार्यक्रमों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक पाउच बेल्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा, परेड के दौरान समीक्षा अधिकारियों के लिए तलवार ले जाने की अनिवार्यता को भी अब पूरी तरह वैकल्पिक बना दिया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव सेना द्वारा जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 नाम के एक नए 174 पन्नों के मैनुअल में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। इससे पहले सेना ने करीब आठ साल पहले अपनी वर्दी को लेकर ऐसा कोई व्यापक और बड़ा मैनुअल जारी किया था। वर्दी में किए गए मुख्य बदलावों की बात करें तो अधिकारियों को पहली बार औपचारिक आयोजनों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है, जिसे पूरी आस्तीन की शर्ट के ऊपर पहना जा सकता है। यह जैकेट ठोस और सौम्य रंग की होगी, जिसे बिना हुक या हुक के साथ पहना जा सकेगा। वहीं महिला अधिकारियों को सौम्य रंगों की साड़ी, कुर्ता-सलवार या दुपट्टे के साथ टखने तक की सीधी पैंट पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि, स्लीवलेस कुर्ते, प्लाजो और सिगरेट पैंट जैसे कैजुअल कपड़ों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सेना ने सभी रैंकों के लिए एक नई विंटर ड्रेस पेश की है, जिसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बेरेट (टोपी) शामिल है।

'बांग्लार बाड़ी' प्रोजेक्ट के 10 हजार अवैध उपभोक्ताओं को वापस लौटाने होंगे पैसे

निज संवाददाता : बांग्लार बाड़ी प्रोजेक्ट के 10 हजार अवैध उपभोक्ताओं को पैसे वापस लौटाने होंगे। इस बाबत हर ज़िले में सूची बनाने का काम चल रहा है। नवान्न सूत्रों के मुताबिक, करीब एक हज़ार फ़ायदेमंदों की पहचान हो चुकी है। इनमें से कुछ ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करके घर लिए हैं, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा घर बने हैं। पूरी सूची को छांटा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले फ़ेज़ में इस प्रोजेक्ट के तहत 12 लाख फ़ायदों में से हर एक को 1 लाख 20 हज़ार रुपये मिले हैं। दूसरे फ़ेज़ में, बांग्लार बाड़ी प्रोजेक्ट के पहले फ़ेज़ का गैर-कानूनी तरीके से फ़ायदा उठाने वाले 16 लाख और लोगों को सरकार को पैसे वापस करने होंगे। राज्य में सरकार बदलने के बाद, नवान्न ने पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, दूसरे फ़ेज़ में गैर-कानूनी तरीके से घर पाने वालों की संख्या पहले फ़ेज़ से ज़्यादा

हर जिले में बन रही है सूची

है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, बांग्लार बाड़ी प्रोजेक्ट का गैर-कानूनी तरीके से फ़ायदा उठाने वालों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया था। राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को लिखे एक पत्र में यह आदेश दिया। पत्र में बताया गया है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करके कई अयोग्य लाभार्थियों को गैर-कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। आगे आरोप है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा घर हैं। इसके अलावा, जिनके पास पक्के घर हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाया है। इस वजह से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस वजह से लाभार्थियों की सूची को नए सिरे से वेरिफाई करना होगा। बाद में एक और पत्र में बताया गया कि प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे फेज के लाभार्थियों को फिर से वेरिफाई करना होगा।नए निर्देशों में कहा गया है कि री-वेरिफिकेशन के दौरान अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की जानकारी फिर से चेक की जा सकती है। हालांकि, जिनकी अयोग्यता की पुष्टि होती है, उनसे प्रोजेक्ट का पैसा वसूलने का इंतजाम किया जाना चाहिए।विभाग ने कहा कि वसूला गया पैसा टीआर फॉर्म-7 के ज़रिए बताए गए ट्रेजरी हेड ऑफ अकाउंट (2216-03-002-001-70-01) में जमा किया जाना चाहिए। पैसे वापस करने के बाद, संबंधित ब्लॉक को रिकवरी मॉड्यूल में बेनिफिशियरी आईडी के हिसाब से वसूली गई रकम दर्ज करनी होगी और टीआर फार्म-7 की कॉपी अपलोड करनी होगी।जिलों को यह री-वेरिफिकेशन और पैसे की रिकवरी का काम जल्दी पूरा करके फाइनल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित जिले में वेरिफिकेशन ठीक से और ध्यान से किया गया है, इसका सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। गौरतलब है कि पिछली सरकार के समय में प्रधानमंत्री आवास योजना में बार-बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कई बार केंद्रीय टीम आवास की जांच करने राज्य में आई थी। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए और पैसे नहीं दिए। फिर पिछली सरकार ने बंगालर बाड़ी प्रोजेक्ट शुरू किया।

यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता में 14 व्यस्त रूटों पर बढ़ाई जाएंगी सरकारी बसें

निज संवाददाता : राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस सेवा शुरू होने के बाद कई महत्वपूर्ण रूटों पर यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग के एक अध्ययन के अनुसार कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि 22 से 25 फीसदी तक पहुंच गई है। नतीजतन, बसों में भीड़भाड़ और यात्रियों की परेशानी की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए कोलकाता के 14 व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त सरकारी बसें चलाने का फैसला किया है। विभिन्न रूटों पर यात्री दबाव की स्थिति की जांच के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया गया था। नया निर्णय उस अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिन रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी उनमें उल्टाडांगा-इको स्पेस (न्यू टाउन), इको पार्क-हावड़ा स्टेशन, उल्टाडांगा-सेक्टर पांच, जादवपुर-करुणामयी, रथतला-हावड़ा स्टेशन, उल्टाडांगा-रूबी, हावड़ा स्टेशन-गरिया, हावड़ा स्टेशन-एयरपोर्ट और रूबी-हावड़ा रूट शामिल हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में, बस ड्राइवर और कंडक्टर महिला यात्रियों को बस स्टॉप पर इंतज़ार करते हुए देखकर भी बसें नहीं रोकते हैं। चूंकि महिला यात्रियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ता, इसलिए यह ट्रेंड देखा जा रहा है। परिवहन विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। सभी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को बताया गया है कि अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो वे जांच करेंगे और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। सर्वे से पता चला है कि कुछ रूट पर महिला यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ऑफिस टाइम के अलावा दूसरे समय में भी बस में खड़े होने की जगह नहीं मिलती। नतीजतन, हर दिन कई यात्रियों को परेशानी हो रही है। विभाग को उम्मीद है कि अगर और बसें चलाई जाती हैं तो इंतज़ार का समय कम होगा और भीड़ काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। अभी, राज्य के पांच ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के तहत 368 रूट पर कुल 1,783 सरकारी बसें चल रही हैं। इसके अलावा, अगले छह महीनों में 50 और इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारने की योजना है। परिवहन विभाग का मकसद धीरे-धीरे सरकारी बसों की संख्या बढ़ाना और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाना है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, महिला पैसेंजर को देखने के बाद भी बसें न रोकने की शिकायत बहुत बुरी है। इसलिए, बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सर्विस की क्वालिटी बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग भी मज़बूत की जाएगी।

जिन रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी उनमें उल्टाडांगा-इको स्पेस (न्यू टाउन), इको पार्क-हावड़ा स्टेशन, उल्टाडांगा-सेक्टर पांच, जादवपुर-करुणामयी, रथतला-हावड़ा स्टेशन, उल्टाडांगा-रूबी, हावड़ा स्टेशन-गरिया, हावड़ा स्टेशन-एयरपोर्ट और रूबी-हावड़ा रूट शामिल हैं।

कोलकाता जल्द बनेगा वॉटर मेट्रो सिस्टम का हिस्सा

17 दूसरे शहरों के नेटवर्क में शामिल होगा महानगर

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को घोषणा की कि कोलकाता को जल्द ही 17 दूसरे शहरों को कवर करने वाले नेशनल नेटवर्क के हिस्से के तौर पर एक वॉटर मेट्रो सिस्टम मिलेगा। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के साथ बैठक के बाद शुभेंदु ने कहा-कोलकाता वॉटर मेट्रो नेटवर्क से जुड़ रहा है। इस नेटवर्क पर 17 शहर हैं। कोलकाता इसमें शामिल होने वाला 18वां शहर होगा। यह प्रोजेक्ट केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय लागू करेगा। वॉटर मेट्रो के सड़क और मेट्रो रेल नेटवर्क के समानांतर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के एक वैकल्पिक तरीके के तौर पर काम करने की उम्मीद है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा-यह आर्थिक रूप से फायदेमंद और इको-फ्रेंडली भी होगा। केरल का कोच्चि दिसंबर 2021 में वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसमें इसकी इलेक्ट्रिक बोट मुज़िरिस कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे बैटरी से चलने वाले बेड़े का हिस्सा है।

कोच्चि सिस्टम 15 रूट पर चलता है, जो 78 किमी में 10 आइलैंड को जोड़ता है, जिसमें तेज़, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी का एक बेड़ा 38 जेट्टी तक जाता है। कोलकाता प्रोजेक्ट के भी इसी तरह के मॉडल को फॉलो करने की उम्मीद है, जिसमें मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कई रूट और फिक्स्ड शेड्यूल होंगे। इस मौके पर शुभेंदु ने पिछली ममता बनर्जी सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि उसने केंद्र सरकार की पहल में हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट हुगली के साथ इनलैंड वॉटरवे रूट का पता लगाएगा और शहर को आस-पास के जिलों से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन का पता लगाएगा। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद पानी पर आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करके सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बंगाल सरकार तैयार कर रही है बड़ा रोडमैप

ईएमसी 2.0 स्कीम के जरिए होगा बुनियादी ढांचे का विस्तार

निज संवाददाता : बंगाल सरकार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े रोडमैप पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार केंद्र सरकार की संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) स्कीम का लाभ उठाकर अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के रास्ते तलाश रही है। इसके तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पिछली योजना के तहत स्थापित नैहाटी और फालता क्लस्टर्स के विस्तार का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब केंद्र सरकार भी घरेलू और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्नोलॉजी कंपनियों को पश्चिम बंगाल में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीजी) में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित कर रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्य में नए निवेश के लिए नए सिरे से जमीन की पहचान शुरू कर दी गई है, लेकिन लैंड बैंक तैयार करने में समय लग सकता है। इसलिए, राज्य सरकार मौजूदा स्थानों पर ही केंद्र की मदद से फंड जुटाने और एंकर इन्वेस्टमेंट सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है। करीब 70 एकड़ में फैले नैहाटी और 58 एकड़ में फैले फालता क्लस्टर्स में पर्याप्त खाली क्षमता मौजूद है। ये दोनों स्थान कोलकाता से महज दो घंटे की दूरी पर हैं। राज्य की ओर से डेटा सेंटर्स और भूमि अधिग्रहण के लिए नई नीतियां तैयार किए जाने के बाद निवेश की बातचीत में और तेजी आने की उम्मीद है। क्या है ईएमसी 2.0 स्कीम? यह स्कीम साल 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत रेडी-बिल्ट फैक्ट्री शेड्स और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट लागत का 50 फीसदी (प्रति 100 एकड़ पर अधिकतम 70 करोड़ रुपये की सीमा के साथ) केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाता है। दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत 10 राज्यों के 13 प्रोजेक्ट में 123 भूमि शामिल थे। चूंकि इस योजना के लिए एप्लिकेशन विंडो मार्च 2024 में बंद हो चुकी है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे हैं कि क्या मौजूदा पुरानी सुविधाओं को इसके दायरे में शामिल किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, पुरानी ईएमसी 1.0 साइट की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय फंडिंग की मांग कर सकती है। अगर केंद्र सरकार से इस विस्तार को मंजूरी मिल भी जाती है, तो राज्य सरकार को बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें इस प्रकार हैं :मौजूदा क्लस्टर्स से सटी कम से कम 100 एकड़ जमीन को न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूरा करने के लिए विचार में लिया जाएगा। मौजूदा क्लस्टर की कम से कम 80 फीसदी बिक्री योग्य या लीज योग्य भूमि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आवंटित होनी चाहिए। इसके अलावा, आवंटित भूमि वाली कम से कम 50 फीसदी यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका होना चाहिए। राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आवेदनों के निपटारे में लगने वाला समय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिकतम 50 दिनों की समय सीमा तय होने के बावजूद, महज तीन आवेदनों को प्रोसेस करने में औसतन 235 दिन का समय लगा है। सरकार अब इस देरी को कम करने पर ध्यान दे रही है।

मंदिरों में पूजा के बाद बचे फूलों और मालाओं से अब बनेगी अगरबत्ती

राज्य सरकार की नई योजना

निज संवाददाता : राज्य में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद, राज्य सरकार एक के बाद एक लोगों से जुड़ी नई पहल कर रही है। अब, पर्यावरण की सुरक्षा और रोज़गार बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, महिला और बाल कल्याण और समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने एक नई योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार अलग-अलग मंदिरों में पूजा के बाद बचे फूलों और मालाओं से अगरबत्ती बनाने की योजना बनाने जा रही है, जिन्हें अब तक बेकार समझकर फेंक दिया जाता था। बीरभूम के मुख्य सिद्धपीठों में से एक तारापीठ मंदिर को इस पहल से उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। तारापीठ में हर दिन हज़ारों भक्त इकट्ठा होते हैं। मां तारा के चरणों में भारी मात्रा में फूल, मालाएं और पूजा का सामान चढ़ाया जाता है। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद, वे फूल आखिर में कचरा बन जाते हैं। लंबे समय से, इन फूलों और पूजा के सामान को फेंकने से तारापीठ इलाके में पर्यावरण प्रदूषण का डर था।एक समय था, जब तारापीठ मंदिर से बचे हुए फूल और पूजा का कचरा मंदिर के पास द्वारका नदी में फेंक दिया जाता था। इस वजह से नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। बाद में, बीरभूम ज़िला

प्रशासन की पहल पर मल्लारपुर का एक एनजीओ इस समस्या को हल करने के लिए आगे आया। पिछले कुछ सालों से, वह संगठन नियमित तौर पर तारापीठ मंदिर से बचे हुए फूल और पूजा का कचरा इकट्ठा कर रहा है और उससे ऑर्गेनिक खाद बना रहा है। संगठन अभी भी हर दिन मंदिर से फूल इकट्ठा कर रहा है। लेकिन, अगर राज्य सरकार का नया प्लान लागू होता है, तो उन बचे हुए फूलों से अगरबत्ती बनाई जाएगी। इससे एक तरफ तो मंदिर इलाके में पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक कंट्रोल होगा, और दूसरी तरफ, रोज़गार के नए रास्ते भी खुलेंगे, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। सिर्फ़ तारापीठ ही नहीं, बल्कि बीरभूम के पांच सतीपीठ- नलहटी में नलतेश्वरी मंदिर, सैंथिया में नंदिकेश्वरी मंदिर, लाभपुर में मां फुलारा मंदिर, बोलपुर में कंकालीतला मंदिर और बकरेश्वर मंदिर समेत ज़िले के कई मंदिरों में हर दिन बहुत ज़्यादा फूल कचरे के तौर पर जमा होते हैं। अगर उन सभी फूलों को रीसायकल करके अगरबत्ती बनाई जा सके, तो न सिर्फ़ मंदिर साफ़ होंगे, बल्कि एनवायरनमेंट-फ्रेंडली पहल के तौर पर भी इसे खास अहमियत मिलेगी। इस बारे में महिला एवं बाल कल्याण और समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा-जिन भी मंदिरों में फूल और फूलों की मालाएं इस्तेमाल होती हैं, उन्हें फालतू में फेंकने के बजाय, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और उन फूलों से अगरबत्ती बनाई जाएगी। वहां कम से कम 15 महिलाओं को काम मिलेगा। हम इसके लिए एक वर्कशॉप लगाएंगे। मेरे डिपार्टमेंट के पास अलग से फंड है, जिससे वर्कशॉप लगाई जाएगी। दूसरी ओर, तारापीठ मंदिर कमेटी के सदस्य और बीजेपी कार्यकर्ता पुलक चटर्जी ने कहा-अगर राज्य सरकार यह पहल करती है, तो मंदिर कमेटी को बहुत फायदा होगा। एक तरफ, मंदिर का बचा हुआ फूलों का कचरा मंदिर परिसर में जमा नहीं होगा, और दूसरी तरफ, कई लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। पहले, इस फूलों के कचरे की वजह से मंदिर परिसर में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही थी। अभी, मल्लारपुर में एक एनजीओ संस्था फूल इकट्ठा करके ऑर्गेनिक खाद बना रही है। मंदिर कमेटी उस संस्था को आर्थिक मदद भी दे रही है। हालांकि, अगर सरकार अगरबत्ती बनाने की पहल शुरू करती है, तो आम लोगों को भी फायदा होगा। आम जनता से लेकर पर्यावरणविदों तक सभी का मानना है कि राज्य सरकार की यह पहल, जो धार्मिक भावनाओं, पर्यावरण जागरूकता और रोजगार को एक साथ जोड़ती है, अगर लागू की गई तो एक नई मिसाल कायम करेगी।

बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्त की सुरक्षा

निगरानी के लिए तैनात किए एआई रोबोट और स्मार्ट ड्रोन

निज संवाददाता : भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) टेक्नोलॉजी पर आधारित निगरानी पर अपना फोकस बढ़ा रही है। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा है कि बॉर्डर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में चेहरे और आंखों की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी वाले सीसीटीवी कैमरे और आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस) कॉप्टर ड्रोन पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा, देसी टेक्नोलॉजी से बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर डोमेन पर आधारित रोबोट के इस्तेमाल का काम भी तेजी से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के बॉर्डर इलाकों में शुरू किया गया है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से बॉर्डर पर गाड़ियों या जानवरों की मूवमेंट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके चलते सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। नए सिस्टम में पहियों या पैदल चलने में सक्षम ऑटोमैटिक रोबोट बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे। वे खराब मौसम, घने कोहरे या रात के अंधेरे में भी अपना काम जारी रख पाएंगे। दूसरी ओर, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ड्रोन एरियल सर्विलांस करेंगे और रियल-टाइम वीडियो और थर्मल इमेज देंगे। एआई-बेस्ड कंप्यूटर विज़न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन से कैप्चर की गई तस्वीरों और वीडियो को एनालाइज़ करने के लिए किया जाएगा ताकि लोगों, गाड़ियों और जानवरों में फ़र्क किया जा सके। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (चेहरे की पहचान तकनीक) का इस्तेमाल संदिग्धों के चेहरों को एनालाइज़ (विश्लेषण) करने और उन्हें अपराधियों के डेटाबेस से मैच करने के लिए भी किया जाएगा। इन्फ्रारेड और रडार टेक्नोलॉजी (अवरक्त और रडार प्रौद्योगिकी) से बारिश, कोहरे या रात में अंधेरे में भी निगरानी की जा सकेगी। इसके अलावा, बॉर्डर के ज़मीन के नीचे फाइबर-ऑप्टिक सेंसर और इन्फ्रारेड लेज़र लगाने की योजना है। जब भी कोई व्यक्ति या गाड़ी हिलेगी, तो यह सेंट्रल कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजेगा। अगर कोई संदिग्ध हरकत पकड़ी जाती है, तो एआई सिस्टम अपने आप उसका पीछा करेगा और ज़रूरत पड़ने पर टारगेट की जगह का पता लगाने के लिए कई ड्रोन और कैमरों को कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसे में, बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की हर दो साल में होने वाली सबसे बड़ी मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। मीटिंग में बॉर्डर पर कांटेदार तार की बाड़ बनाना, घुसपैठ, तस्करी और पकड़े गए घुसपैठियों का एक्सट्रैडिशन जैसे मुद्दे चर्चा के मुख्य टॉपिक बनकर उभरे। भारत का लक्ष्य सिर्फ़ कांटेदार तार पर निर्भर रहने के बजाय स्मार्ट फेंसिंग, एआई, ड्रोन और सेंसर-बेस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए बॉर्डर सिक्योरिटी को ज़्यादा असरदार बनाना है, और घुसपैठ और स्मगलिंग की समस्याओं का लंबे समय का समाधान ढूंढना है।

लंबित रेल परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने बनाया टास्क फोर्स

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने बंगाल में रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास करने और नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल को इसका चेयरमैन बनाया गया है। नवान्न सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय रेल मंत्रालय और राज्य सरकार की यह 20 सदस्यों वाली कमेटी प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नज़र रखेगी। गृह, परिवहन, भूमि और भूमि सुधार, निर्माण समेत कई अहम शीर्ष अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी में ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रेलवे, मेट्रो रेल, रेलवे बोर्ड और आरवीएनएल के प्रतिनिधि भी होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले शनिवार को राज्य के दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले दिनों में बंगाल में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य में चल रहे रेलवे परियोजनाओं में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए। इस टास्क फोर्स का मुख्य मकसद ज़मीन अधिग्रहण, प्रशासनिक समन्वय और परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों को जल्दी हल करना है। निर्देशों में कहा गया है कि परियोजना की प्रगति का हर हफ्ते रिव्यू किया जाएगा और ज़रूरी समाधान किए जाएंगे। निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य सचिव खुद हर महीने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा था कि रुके हुए चिंगरीहाटा मेट्रो का काम सिर्फ 48 घंटे में पूरा कर लिया गया। 70 परियोजनाएं सिर्फ इसलिए लेट हुए क्योंकि उन्हें मंजूरी नहीं मिली। हालांकि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए पिछली ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा-रेलवे की पिछली सरकार के साथ टकराव वाली सोच थी। केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जिससे आम आदमी को फायदा नहीं मिल रहा था। हालांकि, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बार काम और तेजी से आगे बढ़ेगा।

पीएम मोदी तारकेश्वर में करेंगे सभा

निज संवाददाता : 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन राज्य में आ रहे हैं। वे तारकेश्वर में एक सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा से बंगाल के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। बंगाल में बीजेपी सत्ता में है। राज्य में डबल इंजन की सरकार है। राज्य के लोगों को इस बार कई केंद्रीय प्रोजेक्ट्स का फायदा मिलने वाला है। तारकेश्वर के मंच से प्रधानमंत्री उस दिन बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, इस पर कई घोषणाएं कर सकते हैं। मालूम हो कि बीते नौ मई को मोदी ब्रिगेड में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। वे डेढ़ महीने में फिर आ रहे हैं।

स्टूडेंट यूनियन की फीस बंद करने का निर्देश

निज संवाददाता : छात्रों से यूनियन के नाम पर मोटी रकम वसूलना अब नहीं चलेगा। राज्य में सत्ता बदलने के बाद सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और एडेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक डेडलाइन तय की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें अगले 30 दिनों के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। राज्य प्रशासन ने तय समय के अंदर संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार मुख्य रूप से स्टूडेंट यूनियन के चुनाव और फंड में पारदर्शिता के मुद्दे पर ध्यान दे रही है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अभी राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई चुनी हुई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। हालांकि, नियमों के मुताबिक, बिना चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के छात्रों से स्टूडेंट यूनियन के लिए कोई फीस नहीं ली जा सकती। लेकिन अब तक ऐसा ही होता रहा है। इसलिए, स्टूडेंट यूनियन की फीस तुरंत वसूलना बंद करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट यूनियन के लिए अब तक कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, और वह पैसा किन सेक्टर में खर्च किया गया है, इसका डिटेल्ड अकाउंट मांगा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला कॉलेज यूनियन फंड में करप्शन को रोकने के लिए है। राज्य में सत्ता में आते ही प्रशासन पूरे सिस्टम में फैले करप्शन के अड्डे को खत्म करने में लग गया है। पिछली सरकार में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, लगभग हर क्षेत्र में करप्शन के आरोप लगते थे। कई लोगों का कहना है कि सरकार के राज में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आए दिन यूनियनें धड़ल्ले से चल रही हैं। गलत तरीके से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अब राज्य सरकार उस सिस्टम को खत्म करने में लगी है।

20 जून को मनाया जाएगा 'पश्चिम बंगाल दिवस'

कोलकाता में लगेगी श्यामा प्रसाद की मूर्ति

निज संवाददाता : अब से 'पश्चिम बंगाल दिवस' 20 जून को मनाया जाएगा। नवान्न से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। तृणमूल सरकार के समय राज्य में बैशाख के पहले दिन 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाया जाता था। इस पर बंगाल भाजपा की ओर से भी कड़ी आपत्ति जताई गई थी। राज्य में सरकार बदलने के बाद भाजपा सत्ता में आई। तृणमूल सरकार के कई निर्देशों और नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब 'पश्चिम बंगाल दिवस' का दिन भी बदल दिया गया है। अब से 'पश्चिम बंगाल दिवस' 20 जून को मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद की जयंती है। उस दिन मूर्ति के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने नवान्न में यह घोषणा की। बंगाल भाजपा हमेशा 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाने पर जोर देती रही है। तृणमूल कांग्रेस के समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस तारीख को 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाने को तैयार नहीं थीं। वैसे, कई साल पहले 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाने को लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच तनातनी हो गई थी। उस समय राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल थी। उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को बैशाख के पहले दिन 'पश्चिम बंगाल दिवस' घोषित किया था। राज्य सरकार ने भी उसी दिन दिवस मनाया था। हालांकि बंगाल बीजेपी ने 20 जून को अलग से 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाया था। इस बार बदलाव के बाद 20 जून को आधिकारिक तौर पर 'पश्चिम बंगाल दिवस' मनाने की प्रबल संभावना है। सरकारी हलकों में कुछ समय से यह अटकलें चल रही थीं।

नदिया में मिला अन्नपूर्णा का पुरुष लाभार्थी!

निज संवाददाता : लक्ष्मी भंडार के पुरुष लाभार्थी के बाद अब नदिया में अन्नपूर्णा के पुरुष लाभार्थी का पता चला है। इस बीच, महिलाओं के लिए घोषित इस प्रोजेक्ट का पैसा पुरुषों के बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचा, इस बात की खूब चर्चा हो रही है। संजीत विश्वास नदिया के भीमपुर थाने के चांदपुर गांव के रहने वाले हैं। वे पेशे से ग्रामीण डॉक्टर हैं। उन्हें सरकारी वृद्धावस्था भत्ता भी मिलता है। नियम के मुताबिक वे अपना वृद्धावस्था भत्ता निकालने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र गए। पैसे निकालते समय उन्हें पता चला कि उनके खाते में 200 रुपये और आ गए हैं। उनके अकाउंट में अन्नपूर्णा योजना के अकाउंट में बुढ़ापे के पैसे के अलावा 3,000 रुपये और जमा हो गए थे। संजीत खुद हैरान रह गए। उनका कहना है कि उन्होंने कभी अन्नपूर्णा योजना के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और उन्हें इस स्कीम का लाभार्थी भी नहीं माना जाता। इसलिए, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह पैसा उनके अकाउंट में कैसे जमा हुआ। संजीत विस्वास ने कहा-मैं वृद्धावस्था भत्ता के पैसे निकालने गया था। तब मुझे पता चला कि अन्नपूर्णा योजना से 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह पैसा कैसे आया। इसलिए मैंने वह पैसा नहीं निकाला। मैंने सिर्फ वृद्धावस्था भत्ता के पैसे निकाले, जिनका मैं हकदार था। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले के बारे में स्थानीय पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रमुख को बताएंगे। इसके अलावा, अगर यह पैसा सरकारी नियमों के मुताबिक गलती से उनके अकाउंट में आ गया है, तो वह इसे सरकारी खजाने में वापस करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जिले के अलग-अलग हिस्सों से आरोप सामने आए हैं कि सरकारी प्रोजेक्ट का पैसा कई पुरुषों के अकाउंट में आ गया है। स्थानीय लोगों के एक समूह का दावा है कि ऐसी घटनाएं डेटाबेस में गलती या अकाउंट लिंक करने में गलती की वजह से हुई होंगी। हालांकि, इस बारे में अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच, महिलाओं के लिए बने प्रोजेक्ट का पैसा एक पुरुष के अकाउंट में जमा होने को लेकर इलाके में नई चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों ने मामले की जल्द जांच की मांग की है। यह जांच की जा रही है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या कोई और वजह है।

राज्य सरकार ने शुरू किया मदरसों का सर्वे

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने पूरे राज्य के सभी मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) को 5 जुलाई तक जिलेवार रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मदरसों के बारे में सभी जानकारी देने को कहा गया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश प्रशासनिक मकसद के लिए है। राज्य के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि मदरसे की लोकेशन, यह कब बना, यह रजिस्टर्ड था या नहीं, यह कहां और कैसे रजिस्टर्ड हुआ, छात्र, शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मदरसा आवासीय या निजी सहायता प्राप्त है और वहां के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाए। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि मदरसा शिक्षा को लेकर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकें, छात्रों के फायदे के लिए कदम उठाए जा सकें और मेंटेनेंस किया जा सके। इस रिपोर्ट से राज्य सरकार को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि राज्य के मदरसों में कोई गड़बड़ी या गैर-कानूनी काम तो नहीं चल रहा है। नवान्न ने बताया है कि गड़बड़ी पाए जाने पर सही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह भरोसा दिलाया गया है कि इस जानकारी के आधार पर मदरसों में पढ़ाई रोकने या छात्रों को निकालने का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पढ़ाई वैसे ही चलती रहेगी जैसे मदरसों में चल रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले, राज्य की बीजेपी सरकार के मदरसा शिक्षा विभाग ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले नमाज़ के दौरान वंदे मातरम ज़रूरी तौर पर गाया जाना चाहिए। मदरसा शिक्षा विभाग ने यह अनुदेश 19 मई को जारी किया था। अनुदेश में कहा गया है कि हर दिन स्कूल असेंबली (प्रार्थना) या नमाज़ के दौरान वंदे मातरम ज़रूरी तौर पर गाया जाना चाहिए।

फिर से शुरू की जाएंगी रुकी हुई केंद्रीय ग्रामीण परियोजनाएं

- पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने किया ऐलान
- बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी ज़्यादा अहमियत

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में तृणमूल के शासन के समय में लंबे समय से रुके हुए कई केंद्रीय परियोजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने गुरुवार को नवान्न में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवंटन आने के साथ ही अलग-अलग ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट्स तेज़ी से लागू होने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे रोज़गार, आवास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में नई रफ़्तार आएगी। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2022 से राज्य में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए केंद्रीय आवंटन लगभग बंद था। मंत्री ने कहा कि राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत कई ज़रूरी केंद्रीय परियोजनाओं को फिर से शुरू किया गया है। इनमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (एमएसएपी) और केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अलग-अलग स्कीमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण संचार प्रणाली विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि 27 मई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एम्पावर्ड कमेटी (अधिकार प्राप्त समिति) की मीटिंग में पश्चिम बंगाल के लिए इन-प्रिंसिपल अप्रूवल (सैद्धांतिक अनुमोदन) मिल गया है। प्लान के मुताबिक, राज्य में करीब 2,790 किमी नई ग्रामीण सड़कें और 45 पुल बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य के करीब 2,500 करोड़ रुपये के संयुक्त खर्च से पूरा किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, औपचारिक अनुमोदन मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।सबसे ज़रूरी ऐलान 100 दिन के काम के प्रोजेक्ट को लेकर है। मार्च 2022 से लगभग बंद पड़े मनरेगा (ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की पहल शुरू कर दी गई है। राज्य के करीब 2 करोड़ 56 लाख जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिलाने के लिए हर ग्राम पंचायत में काम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक अनुमोदन, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता निर्माण) का काम भी आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत: रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। मौजूदा मनरेगा स्ट्रक्चर जून तक लागू रहेगा और नया प्रोजेक्ट जुलाई से शुरू होगा। नए सिस्टम के तहत, योग्य परिवारों को साल में 125 दिन की मज़दूरी वाली नौकरी का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, 60 दिन की बेरोजगारी के लिए कानूनी सुरक्षा का सिस्टम भी होगा। केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में प्रोजेक्ट का खर्च उठाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। हर ग्राम पंचायत में असली बेनिफिशियरी (लाभार्थी) की पहचान के लिए घर-घर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे 20 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद, वेरिफिकेशन, ग्राम सभा की मंज़ूरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल (जिला स्तर) पर फाइनल अप्रूवल के बाद बेनिफिशियरी की सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के फिर से शुरू होने से राज्य की रूरल इकॉनमी, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अहम भूमिका होगी।

'मां कैंटीन' अब 'मां आहार'

हफ़्ते में दो दिन अंडे और दो दिन मछली मिलेगी

निज संवाददाता : ममता बनर्जी के राज में शुरू हुई मां कैंटीन का नाम अब मां आहार हो गया है। बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने मां कैंटीन का नाम बदल दिया है। अब यह प्रोजेक्ट बड़े स्तर पर शुरू होने जा रहा है। अब राज्य के सभी हिस्सों में पांच रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। सरकार ने कुल 500 मां आहार सेंटर खोलने का ऐलान किया है। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब से मां कैंटीन का नाम मां आहार होगा। पूरे राज्य में 500 और मां आहार सेंटर खोले जाएंगे। वहां लोग पांच रुपये में पेटभर लंच करेंगे। वहीं, मां आहार का मेन्यू भी बदला जा रहा है। अब से मां आहार सेंटर से हफ्ते में दो दिन मछली और दो दिन अंडे दिए जाएंगे। बाकी तीन दिन शुद्ध शाकाहारी खाना दिया जाएगा। यह जानकारी राज्य की मंत्री अगिनमित्रा पाल ने दी।मालूम हो कि राज्य में सरकार बदलने के बाद सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार ने कहा था कि राज्य में कोई भी सोशल प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। कम से कम, आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। बल्कि, उन्हें और बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। इसी तरह, मां कैंटीन ने मां आहार के रूप में एक नए रूप में अपनी शुरुआत की है। गौरतलब है कि मां कैंटीन प्रोजेक्ट को तृणमूल सरकार ने 2021 में पश्चिम बंगाल के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 5 रुपए में दोपहर का खाना देने के लिए शुरू किया था। ममता राज में मां कैंटीन में 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी और अंडे मिलते थे।

कुछ दिन पहले राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने दावा किया था कि मां कैंटीन में गरीब लोगों को मछली और चावल खिलाया जाएगा। इसी तरह, इन केंद्रों में हफ्ते में दो दिन मछली और चावल परोसा जाएगा। अब शुभेंदु सरकार ने मां आहार का सात दिन का मेन्यू तय कर दिया है।

संपादकीय

विकास में गृहणियों के योगदान को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में गृहणियों को ''राष्ट्र निर्माता'' की संज्ञा दी। सर्वोच्च अदालत का यह मानना, लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कमज़ोरी पर रोशनी डालता है। हाल ही में एक मोटर दुर्घटना में एक गृहिणी की मौत पर मुआवज़े पर एक फैसले में, कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिना पैसे वाले घरेलू देखभाल के काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीना होनी चाहिए, जिसमें हर तीन साल में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह फैसला एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे नकारा नहीं जा सकता। घर, लेबर मार्केट और अर्थव्यवस्था बहुत सारे बिना पैसे वाले काम से चलते हैं, जो ज़्यादातर औरतें करती हैं। टाइम यूज़ सर्वे के डेटा से पता चलता है कि भारतीय महिलाएं दिन में सात घंटे से ज़्यादा बिना पैसे वाले घरेलू और देखभाल के काम में बिताती हैं, जो मर्दों से कई गुना ज़्यादा है। कोर्ट के बताए गए अनुमानों के मुताबिक, औरतों के बिना पैसे वाले देखभाल के काम की कीमत भारत की जीडीपी का 15-17 फीसदी है। फिर भी यह मेहनत पारंपरिक आर्थिक अकाउंटिंग से गायब है और सार्वजनिक नीति में काफी हद तक दिखाई नहीं देती। घरेलू देखभाल को एक मॉनेटरी कीमत देकर, कोर्ट ने इस सोच को चुनौती दी है कि आर्थिक उत्पादकता तभी शुरू होती है जब मज़दूरी दी जाती है। इससे यह बात और पक्की होती है कि देखभाल, बच्चों की परवरिश, घर का मैनेजमेंट और बुज़ुर्गों की देखभाल से ह्यूमन कैपिटल बनता है, वेतनभोगी कार्यबल को बनाए रखा जाता है, और बड़ी आर्थिक गतिविधि को सहारा मिलता है।लेकिन सिर्फ़ पहचान देना काफ़ी नहीं है। गृहणियों को सपोर्ट करने का आर्थिक तर्क ज़बरदस्त है। महिलाओं के हाथ में सीधी इनकम आने से घर का उपभोग ऐसे तरीकों से बढ़ता है जिससे लंबे समय तक वेलफ़ेयर मज़बूत होता है, खासकर न्यूट्रिशन, हेल्थकेयर और एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करके। अंतरराष्ट्रीय सबूत बताते हैं कि इनकम पर महिलाओं का कंट्रोल बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और हेल्थकेयर और घरेलू रिसोर्स तक पहुंच को बेहतर बनाकर मां और बच्चे की मौत की दर को कम करने में मदद कर सकता है। बड़ा नीतिगत सवाल यह है कि पेमेंट किसे करना चाहिए। मॉडल अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, वेनेज़ुएला संवैधानिक रूप से घर के काम की इकोनॉमिक वैल्यू को पहचानता है और सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट देता है। कैश स्टाइपेंड (नकद वजीफा) जिसमें कुछ भारतीय राज्यों द्वारा शुरू की गई स्कीमें शामिल हैं, पहचान का एक रूप हैं लेकिन संरचनात्मक सुधार की जगह नहीं ले सकते। सिर्फ़ पेमेंट से यह सोच भी पक्की हो सकती है कि घरेलू काम सिर्फ़ महिलाओं की ज़िम्मेदारी है। एक गंभीर जवाब के लिए सस्ती बाल देखभाल, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, बेहतर सार्वजनिक सेवा, श्रम बाज़ार में लचीलापन, सुरक्षित कार्यस्थल और ऐसी नीति की ज़रूरत है जो घरों के अंदर देखभाल की ज़िम्मेदारियों को फिर से बाँटें। कोर्ट ने पहचान दी है। सरकारों को अब इसे आर्थिक अधिकारों और सामाजिक अवसंरचना में बदलना होगा, जो देखभाल के काम को कम करे, उसे फिर से बांटे और इनाम दे, साथ ही महिलाओं के लिए मौके भी बढ़ाए।

जब हास्य का पैमाना बन जाए केवल भीड़ का ठहाका

व्यूज की अंधी दौड़ में लहूलुहान होती सामाजिक मर्यादा

अजय कुमार

गुरुग्राम के एक स्टैंडअप कॉमेडी शो में 370 रुपए की बिरयानी की कीमत एक महिला की अस्मिता से लगाने वाले दर्शक का वीडियो और उस पर ताली पीटते कॉमेडियन प्रणीत मोरे का ठहाका सिर्फ एक तात्कालिक विवाद नहीं, बल्कि भारतीय स्टैंडअप कॉमेडी के उस गहरे नैतिक और वैचारिक पतन का दस्तावेज़ है, जो पिछले एक दशक से धीरे-धीरे हमारे समाज में पैठ बना रहा था। यह घटना साफ तौर पर रेखांकित करती है कि व्यूज, लाइक्स और वायरल क्लिप्स की अंधी दौड़ में हास्य और अश्लीलता के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जहां दर्शक हिमांशु जांगड़ा की नौकरी चली गई, वहीं प्रणीत मोरे को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर माफी मांगनी पड़ी। वहीं, दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदर से लेकर अभिनेत्री रश्मि देसाई तक ने इस खोखली माफी को सिरे से खारिज कर दिया। विवाद केवल यहीं नहीं थमा; इसी शो की एक अन्य क्लिप में एक महिला मेडिकल छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर मज़ाक बनाने की बात गर्व से कबूल की, जिसने चिकित्सा जगत की नैतिकता और देहदान करने वाले परिवारों की भावनाओं को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यह अराजकता किसी एक मंच की नहीं, बल्कि उस क्राउडवर्क फॉर्मेट की देन है, जहां बिना स्क्रिप्ट, बिना सेंसर और बिना संपादन के केवल तात्कालिक भीड़ को हंसाने के लिए किसी भी हद तक जाने की खुली छूट ले ली गई है। भारतीय स्टैंडअप कॉमेडी का इतिहास पिछले एक दशक में जितनी तेज़ी से व्यावसायिक रूप से समृद्ध हुआ है, वैचारिक और सामाजिक रूप से वह उतना ही सतही और खोखला होता गया है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पूरा एल्गोरिदम रचनात्मकता से ज्यादा शॉक वैल्यू और विवाद को बढ़ावा देता है। जब कलाकार को पता होता है कि जितना तीखा, अभद्र या विवादास्पद कंटेंट होगा, रील्स और शॉर्ट्स पर उतने ही मिलियन व्यूज मिलेंगे, तो वह सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रख देता है। अभिनेत्री रश्मि देसाई और आयशा खान का यह सवाल बेहद मौजूं है कि जब एक महिला की गरिमा को मंच पर तार-तार किया जा रहा था, तब उस हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं था, जो उठकर इसका विरोध करता? सामूहिक हंसी अक्सर व्यक्तिगत विवेक को सुला देती है और यही इस डिजिटल इकॉनॉमी का सबसे खतरनाक पहलू है। जब हास्य का पैमाना केवल भीड़ का ठहाका बन जाए, तो वह कला नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित तमाशा बन जाती है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों और इतिहास पर नज़र डालें, तो स्टैंडअप कॉमेडी का यह भटकाव हर दिशा में फैला है, चाहे वह धर्म हो, देश की सुरक्षा एजेंसियां हों, सेना हो या फिर लोक संस्कृति। साल 2021 में मुनव्वर फारुकी को इंदौर में हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणी के आरोप में करीब एक महीना जेल में बिताना पड़ा था। इसके बाद 2023 में भारतीय मूल की अमेरिकी कॉमेडियन जरना गर्ग का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने 19,000 हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाया, जिसके खिलाफ देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला और कई राज्यों में एफआईआर की मांग की गई। साल 2024 में पुनः मुनव्वर फारुकी को मुंबई के एक शो में कोंकणी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए लिखित माफी मांगनी पड़ी। वर्ष 2025 में यह विवाद चरम पर पहुंच गया, जब महाराष्ट्र में महज दो महीनों के दौरान कुणाल कामरा, समय रैना और प्रणीत मोरे पर अलग-अलग मामलों में गंभीर एफआईआर दर्ज हुईं। कुणाल कामरा द्वारा राजनीतिक नेतृत्व पर किए गए कटाक्ष के बाद मुंबई के हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ हुई और बीएमसी की कार्रवाई झेलनी पड़ी। इसी तरह अतीत में तन्मय भट्ट द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मज़ाक उड़ाने पर भारी कानूनी और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि आंध्र प्रदेश में कॉमेडियन अनुदीप को अभिनेता व नेता पवन कल्याण पर की गई टिप्पणी के कारण पुलिस हिरासत में जाना पड़ा।यह पूरा परिदृश्य दिखाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एकतरफा ढाल तैयार की जा रही है। जब राजनेताओं, पुलिसकर्मियों या सेना के जवानों पर व्यंग्य किया जाता है, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार का नाम दिया जाता है, लेकिन जब इसी स्वतंत्रता का उपयोग किसी मृत देह के अपमान, किसी समुदाय की अस्मिता को ठेस पहुंचाने या महिला विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तब इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? देश में हर साल हजारों स्टैंडअप शो होते हैं और इनके वीडियो यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर करोड़ों की कमाई करते हैं। इस विशाल बाजार की अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। एक जीवंत लोकतंत्र में सत्ता, रूढ़ियों और पाखंड पर तीखा कटाक्ष होना अनिवार्य है और भारत में ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं, जो मर्यादा में रहकर यह काम करते हैं। परंतु जब पूरी इंडस्ट्री को एक ही तराजू में तौला जाता है, तो नुकसान उन वास्तविक कलाकारों का होता है, जो कला की समझ रखते हैं।

हास्य का मूल उद्देश्य समाज को आईना दिखाना और तनाव कम करना होता है, न कि किसी की गरिमा को कुचलना। सरकार या अदालतें कानून बनाकर मंच पर सेंसरशिप लागू नहीं कर सकतीं और न ही यह एक स्वस्थ समाज के लिए सही होगा। इसकी अंतिम रेखा उस दर्शक को ही खींचनी होगी, जो टिकट खरीदकर इन शो में बैठता है। जब तक दर्शक अश्लीलता, अभद्रता और संवेदनहीनता पर तालियां बजाना बंद नहीं करेंगे, तब तक व्यूज की भूख से तड़पते ये क्रिएटर मर्यादाओं को लांघते रहेंगे।

प्रणीत मोरे का यह कहना कि वह इंसान हैं और सीख रहे हैं, एक पेशेवर मंच पर अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। यदि वीडियो को एडिट कर, उस पर आकर्षक टैग लगाकर जानबूझकर वायरल किया गया, तो कॉमेडियन इस प्रकरण में बराबर का भागीदार है। हास्य का मूल उद्देश्य समाज को आईना दिखाना और तनाव कम करना होता है, न कि किसी की गरिमा को कुचलना। सरकार या अदालतें कानून बनाकर मंच पर सेंसरशिप लागू नहीं कर सकतीं और न ही यह एक स्वस्थ समाज के लिए सही होगा। इसकी अंतिम रेखा उस दर्शक को ही खींचनी होगी, जो टिकट खरीदकर इन शो में बैठता है। जब तक दर्शक अश्लीलता, अभद्रता और संवेदनहीनता पर तालियां बजाना बंद नहीं करेंगे, तब तक व्यूज की भूख से तड़पते ये क्रिएटर मर्यादाओं को लांघते रहेंगे। समय आ गया है कि डिजिटल युग की इस बर्बर हंसी के खिलाफ समाज स्वयं अपनी मूक सहमति को तोड़े और यह तय करे कि मनोरंजन के नाम पर किस हद तक नीचे गिरने की इजाजत दी जा सकती है।

जानें अपना राशिफल

मेष

फायदेमंद समय हो सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी के साथ मिलकर काम करने पर विचार हो सकता है जो लाभदायक होगा, अपने परिवार को प्रसन्न रखे, मन शान्त रखे।

वृषभ

तरक्की करने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, मन में विश्वास रखे।

मिथुन

खाने पीने का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं तो बीमार भी हो सकते हैं, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है, मन शान्त रखे।

कर्क

प्रभावशाली समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, मन स्थिर रखे।

सिंह

आशा भरा समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, मन शान्त रखें।

कन्या

परिपूर्ण समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन स्थिर रखे।

तुला

काम–धन्धे वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई विदेश में व्यापार करने पर विचार हो सकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक

कुशलता वाला समय हो सकता है, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य करने पर विचार हो सकता है, किसी यात्रा पर जाने का विचार भी हो सकता है, मित्र पूरा साथ दे सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा।

धनु

सहायता मिलने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपने विचार स्पष्ट रखकर काम करे, मन स्थिर रखें।

मकर

भ्रमण करने वाला समय हो सकता है, किसी के साथ मिलकर काम करने पर विचार हो सकता है जो फायदेमंद होगा, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है, मन शान्त रखें।

कुंभ

हिम्मत वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी विदेश यात्रा करने पर विचार हो सकता है, मन में उत्साह रहेगा।

मीन

कठिनाई आने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है, आपसी सहमति बनाये रखें, मन शान्त रखे।

मूर्ख मगरमच्छ और गीदड़ की कहानी

बहुत पुरानी बात है एक तालाब में एक मगरमच्छ और कछुआ रहते थे। उसी तालाब में एक गीदड़ पानी पीने आया करता था। मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियां खाकर खत्म कर दी अब तालाब में कोई भी मछली नहीं बची थी। मगरमच्छ को खाना न मिलने से अब मगरमच्छ को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगी थी वह सोचने लगा - ''मैंने तो तालाब की सारी मछलियां खाकर खत्म कर दीं, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या खाऊं। एक गीदड़ रोज यहाँ आता था आज वह भी पानी पीने नहीं आया। कुछ देर बाद कछुआ मगरमच्छ के पास आकर पूछता है- ''भाई मगरमच्छ! आज तुम बहुत उदास लग रहे हो क्या बात है। मगरमच्छ कछुए की बात सुन कर कहता है - '' मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खाने के लिए तालाब में मछलियां नहीं बची है। मैं सोच रहा था कि यदि गीदड़ पानी पीने आता तो उसी से अपनी भूख मिटा लेता, किंतु वह तो बहुत चालाक है और यहां पानी पीने नहीं आ रहा है।'' मगरमच्छ की बात सुनकर कछुआ कहता है- '' भाई मगरमच्छ ! इस तालाब की सारी मछलियाँ तो तुमने पहले ही ख़त्म कर दी हैं और गीदड़ भी तुम्हारे डर से यहाँ नहीं आता। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ ? मगरमच्छ कछुए से बोला - '' भाई कछु तुम तो मेरे परम मित्र हो, क्या ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने मित्र का साथ नहीं दोगे। कुछ ऐसा उपाय करो कि गीदड़ खुद पर खुद मेरे पास चला आये। कछुआ बोला- '' मित्र तुम्हे तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं

कुछ उपाय करता हूं। तुम एक काम करना, मैं किसी तरह गीदड़ को यहां लेकर आता हूं और तुम सांस रोके हुए ऐसे पड़े रहना जैसे कि मर गए हो। '' मगरमच्छ कछुए की बात समझ गया और तालाब में सांस रोके हुए पड़ा था जैसे मार गया हो। कुछ ही देर में गीदड़ वहां से गुजरता है। गीदड़ को देखकर कछुआ जोर-जोर से रोने लगता है। कछुए के रोने की आवाज सुनकर गीदड़ कछुआ के पास आकर पूछता है- '' भाई कछुआ! क्या हुआ तुम इतना क्यों रो रहे हो? '' कछुआ बोला '' मेरा मित्र मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं रहा मैं उसी की याद में रो रहा हूं।''गीदड़ मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ यह मगरमच्छ मर गया अब मैं निश्चिंत होकर पानी पी सकता हूं। अब मुझे कोई डर नहीं है। तभी कछुआ गीदड़ से कहता है - '' चलो भाई गीदड़ इस मगरमच्छ के ऊपर कुछ घास पत्तियां डालकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।'' गीदड़ मगरमच्छ के पास जा ही रहा था तभी उसे प्रतीत होता है की मगरमच्छ अभी मरा नहीं है और कछुआ उसे बेवकूफ बना रहा है । कुछ सोचकर गीदड़ कछुआ से बोला -'' भाई कछुआ! मैंने सुना है कि मगरमच्छ की पूँछ मरने के बाद भी हिलती रहती है लेकिन इसकी पूछ तो नहीं हिल रही है। लगता है मगरमच्छ अभी मरा नहीं है।'' यह सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अगर मैं पूछ नहीं हिलाऊंगा तो गीदड़ को यह लगेगा कि मैं जिंदा हूं और वह भाग जाएगा। इतना सोचकर मगरमच्छ अपनी पहुंच हिलाने लगता है। मगरमच्छकी पूँछ हिलती देखकर गीदड़ दूर भाग जाता है और कछुए से कहता है- '' देखो अपने मित्र को वह जिंदा है। तुम दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। '' इतना कहकर गीदड़ वहां से भाग जाता है। कछुआ मगरमच्छ से झल्लाते हुए कहता है, अपनी आंखें खोल दो गीदड़ तो भाग गया है तुम बिल्कुल मुर्ख हो जो गीदड़ की चाल में आ गए मूर्ख हमेशा मुर्ख ही रहता है।

शिक्षा- बुद्धिमानी से बड़ी से बड़ी कठनाई से बचा जा सकता है।

हल करो हीरो बनो

1. इनमे से किस कीट का नाम अंग्रेजी नाम एक तैराक स्ट्रोक का भी नाम है?
(क) कोच्क्रोच (ख) बटरफ्लाई
(ग) एंट (घ) बीटल
2. इनमे से किस शब्द का अर्थ ''कहानी'' होता है?
(क) आत्मा (ख) उपनाम
(ग) कथा (घ) सहायता
3. इनमे से कौन एक पेशेवर क्रिकेटर है?
(क) अश्विनी पोनप्पा (ख) शेफाली वर्मा
(ग) सानिया मिर्जा (घ) अंकिता रैना
4. वान गार्ग संग्रहालय आपको किस शहर में मिलेगा?
(क) एम्स्टर्डम (ख) लन्दन
(ग) केप टाउन (घ) सिडनी
5. धानवाड़ और विजयनगर जिले किस राज्य में है?
(क) मध्य प्रदेश (ख) ओडिशा
(ग) गोवा (घ) कर्नाटक

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची–28

5	3	6			2		7	
	7			9	5	8		
	2	8						
		1			6			
3		2				5		4
			4			1		
						3	4	
		3	1	4			2	
	6		2			9	1	5

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

मार लो मुस्की

एक पति कि दर्दनाक कहानी
कल शाम मैं और मेरी पत्नी बैठक में बैठे थे, तभी हमारी नई, सुन्दर सी पड़ोसन हमारे घर आई...
पत्नी ने हमारा परिचय दिया तो वो अवाक् सी बोली...अरे...ये... ये आपके पति हैं.?
पत्नी बोली - क्यों क्या हुआ?
पड़ोसन - नहीं कुछ नहीं... पत्नी बोली - अरे हुआ क्या, बताओ ना? पड़ोसन शर्माते हुए बोली - बड़े ही हैंडसम हैं..
अब आप ही बताओ... इसमें रात को, मुझे भूखा रखने की क्या बात हुई भला...?

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर: बिजली कहां से आती है?
टीटू : सर, मामाजी के यहां से।
टीचर: वो कैसे?
टीटू : जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं, सालों ने फिर बिजली काट दी।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

रविवार को पति मेडिकल स्टोर पर भागते हुए गया।
पति - भाई साहब! मेरी बीवी सारा दिन चूं चपड़ करती रहती है। केमिस्ट - तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।
पति - कोई ऐसी दवा दीजिए, जिससे उसकी चूं चपड़ बंद हो जाए।
केमिस्ट - भाई, ऐसी कोई दवा होती तो मैं सेंडो को दुकान खोलकर क्यों बैठता।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

गोलू- (पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके) सर मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है.
इंस्पेक्टर - अरे, कौन दे रहा है?
गोलू- सर, बिजली वाले... बार-बार कह रहे हैं, बिल नहीं भरा तो काट देंगे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर: पप्पू, बताओ कबीरदास ने क्या कहा है?
पप्पू: सर, कबीरदास जी ने कहा है कि, ''बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर''।
टीचर: वेरी गुड! इसका मतलब क्या है?
पप्पू: मतलब ये है सर कि... अगर आप बड़े आदमी बन गए और किसी के काम नहीं आए, तो आप बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह बेकार हैं!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पति- ये सब्जी कैसी बनाई है? न नमक है, न मिर्च और न कोई स्वाद काम में तुम्हारा मन नहीं लगता।
पत्नी घूरते हुए बोली- पहले.. खुद की आखों के सामने से मोबाइल हटाओ, बहुत देर से देख रही हूं.. पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रहे हो।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?
भोलू- मैम, मुझे बर्ड फ्लू हो गया था।
टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।
भोलू- आपने इंसान समझा ही कहां। रोज तो मुर्गा बनाती हो..

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पत्नी- सुनो मेरे मुहं में मच्छर चला गया, अब क्या करूं?
पति- पगली ऑल आउट पी ले।
छह सेकंड में काम शुरू।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पति ने बर्थडे पर पत्नी को कार की चाबी देकर कहा-''स्वीट हार्ट ध्यान से गाड़ी ड्राइव करना, दुर्घटना होने पर ये अख़बार वाले उम्र भी छापते हैं।''

माथापच्ची 27 का हल

8	6	2	5	9	3	7	1	4
4	5	1	6	8	7	2	3	9
9	7	3	4	1	2	8	6	5
3	8	5	1	7	4	9	2	6
1	2	4	9	6	5	3	7	8
6	9	7	2	3	8	5	4	1
2	3	6	8	4	9	1	5	7
7	1	9	3	5	6	4	8	2
5	4	8	7	2	1	6	9	3

बॉर्डर पर कंटीली तार पार करके बन गया अरबपति!

- हावड़ा में उजागर हुआ बांग्लादेशी दंपति का स्कैंडल
- जांच में जुटी पुलिस

निज संवाददाता : हाल ही में हावड़ा के जगाछा के उनसानी से एक बांग्लादेशी दंपति को पकड़ा गया था। इस बीच, पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि बांग्लादेशी दंपति कैसे डाब और ताड़ बेचकर दो मंजिला मकान और लॉरी का मालिक बन गया। इस बात की जांच शुरू होते ही पुलिस के सामने कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। पुलिस को पता चला है कि दस दिन पहले पकड़े गए बांग्लादेशी दंपति रमजान गाजी और सदीना बेगम दूब और ताड़ बेचने के अलावा प्रमोशन के धंधे में भी शामिल थे। इसके बाद गिरफ्तार कपल रातों-रात अमीर बन गया। वे करोड़पति भी बन गए। गिरफ्तार बांग्लादेशी दंपति ने जमीन भी खरीदी और दो मंजिला मकान का मालिक बन गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, वे ट्रांसपोर्टेशन के धंधे में भी आ गए। उन्होंने एक लॉरी खरीदी। सवाल उठता है कि गिरफ्तार रमजान के पास इतनी बड़ी रकम कैसे आई? क्या यह पैसा उसके पास किसी तरह बॉर्डर पार से आया? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस यह भी देख रही है कि गिरफ्तार रमजान और सदीना के सिर पर किसी असरदार जिला तृणमूल लीडरशिप का हाथ तो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हावड़ा में एक प्रशासनिक बैठक की। उस बैठक से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें तुरंत होल्डिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। उस समय जगाछा के उनसानी इलाके से रमजानी गाजी और सदीना बेगम को पकड़ा गया। कई और घुसपैठिए पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि यह कपल करीब 14 साल पहले बांग्लादेश से गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसा था। वे सबकी नजरों से बचकर यहीं स्थाई रूप से रहने लगे थे। घटना की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जगाछा से पकड़ा गया कपल 14 साल पहले बांग्लादेश के सतखीरा जिले के रतनपुर इलाके से बॉर्डर पार करके ब्रोकर्स के जरिए इस देश में आया था। फिर वे जगाछा के उनसानी में किराए के मकान में रहने लगे। शुरुआत में यह परिवार इलाके में दाब और ताड़ बेचता था। दाब और ताड़ बेचना छोड़ने के बाद परिवार के मुखिया रमजान को लोकल प्रमोटर्स से करीबी के कारण पुराने मकान को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बाद में वह यही काम करता था। पुलिस ने बताया कि इस बीच उस आदमी ने एक लॉरी खरीदी। उस लॉरी में वह टूटे हुए घरों का सामान उठाकर अलग-अलग जगहों पर तालाब भरने के लिए बेचता था। इस बारे में हावड़ा सिटी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया- गिरफ्तार बांग्लादेशी से अलग-अलग चरणों में पूछताछ की जा रही है। लेकिन रमजान इतने सालों में इतने लाखों रुपये का मालिक कैसे बन गया, इसकी जांच की जा रही है।

राज्य में नेताओं की एग थेरेपी के बीच बढ़ी अंडे की कीमत

निज संवाददाता : राज्य की राजनीति में अंडा कल्चर की गहमागहमी के बीच पोल्ट्री के अंडों की कीमत अचानक बढ़ गई है। व्यापारियों और अंडा संगठन के अधिकारियों को मानसून में भी कीमत कम होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने के साथ-साथ मौसम की मार से अंडे के प्रोडक्शन में भी कमी आई है। यही कीमत बढ़ने का मुख्य कारण है। ऐसे में, क्या जनता लालची नेताओं की एग थेरेपी में अपना पेट बर्बाद करने के बजाय खुद के न्यूट्रिशन पर ध्यान देगी? अब यही बड़ा सवाल है।जून की शुरुआत में अंडों की एक ट्रे की कीमत 180 रुपए थी। महीने के बीच तक यह बढ़कर 220-230 रुपए हो गई। अंडों की कीमत में इस बढ़ोतरी पर वेस्ट बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन माइती ने कहा-तेज गर्मी,ईंधन की कीमत और मजदूरों की मुश्किलों की वजह से अंडों की कीमत बढ़ रही है। शहर और गांव में अंडे बांटने वाले ट्रक और लॉरी ड्राइवरों के रहने और खाने का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। गर्मी में भी काम करने की वजह से उनकी सैलरी बढ़ रही है। कुल मिलाकर, मार्केट में अंडों की कीमत बढ़ रही है। अगर सरकार ईंधन की कीमतें कम कर दे, तो अंडों की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी। अंडों की कीमत सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में भी बढ़ रही है। हालांकि, कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि उन्हें 5 टका में पूरी ज़िंदगी के लिए अंडे मिल जाएंगे। उन्हें यह गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में अंडों की कीमत भी बढ़ेगी। मंत्री दिलीप घोष ने इस कीमत बढ़ोतरी में तृणमूल नेताओं के सामने हाल ही में सड़े हुए अंडों की बिक्री का मुद्दा फिर उठाया है। गौरतलब है कि गरियाहाट में सड़े हुए अंडे के कार्टन कम कीमत पर मिल रहे हैं। कभी-कभी तो ये मुफ़्त में भी दिए जाते हैं। बेहाला बाज़ार के एक वेंडर ने कहा- पिछले हफ़्ते अंडों का होलसेल प्राइस कई गुना बढ़ गया है। हमें रिटेल मार्केट में इन्हें ज़्यादा दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गरियाहाट के एक वेंडर के मुताबिक-खरीदार प्राइस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स को भी ज़्यादा दामों पर अंडे खरीदने पड़ रहे हैं।मार्केट में 30 अंडों के एक कार्टन की कीमत 210 से 215 रुपए तक पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से अनाज और तेल की कीमतों को लेकर लोगों में संकट बना हुआ है। इस बार अंडे भी उसमें शामिल हो गए हैं। राज्य में सब्ज़ियों की कीमत 26 परसेंट से बढ़कर 53 परसेंट हो गई है, जबकि तेल की कीमत 155 से बढ़कर 321 प्रति लीटर हो गई है। अंडों की कीमत जून के बीच से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। अब हर अंडे की कीमत 6.50 रुपए, एक दर्जन की 78 रुपए और 100 अंडों की 650 रुपए है। होलसेल मार्केट में अंडों के सात कार्टन की कीमत करीब 1450 रुपए तक पहुंच गई है। रिटेल मार्केट में हर अंडा 8 से 9 रुपए में बिक रहा है। आमतौर पर सर्दियों में केक, बेकरी और कई तरह के खाने बनाने के लिए अंडों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी और मानसून के मिले-जुले मौसम में अंडों की कीमत बढ़ने की उम्मीद वाकई हैरान करने वाली है।बताया जाता है कि इस बार अंडों की कीमत बढ़ने की मुख्य वजह प्रोडक्शन में कमी के अलावा तेज गर्मी और हल्की बारिश है। प्रोडक्शन में कमी से पोल्ट्री में अंडा देने की दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ रहा है। ज्यादातर अंडे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लाए जाते हैं, जिससे फ्यूल महंगा होने से व्यापार में दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर, अंडा विक्रेताओं ने कहा कि मक्का और सोयाबीन जैसे मुख्य खाने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से अंडा प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है।

निकर में जहांगीर खान की पुलिस ने कराई परेड

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जहांगीर खान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने निकर में उनकी इलाके में परेड कराई थी। अब डायमंड हार्बर पुलिस ने उनके खिलाफ एक और केस खोल दिया है। यह केस 2020 में डायमंड हार्बर में बीजेपी नेता जे. पी. नड्डा पर हुए हमले से जुड़ा है। इस मामले में एफआईआर हुई थी। जहांगीर खान को एफआईआर में नामजद किया गया था लेकिन ममता बनर्जी सरकार में हुई पुलिस की जांच में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था और केस बंद कर दिया गया था। अब पुलिस इस केस को फिर खोलकर जांच करने जा रही है। पुलिस ने बीते गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को, जिन्हें 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता इलाके में कुछ जगहों पर ले गई थी। पुलिसकर्मियों और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की टीमों के साथ जहांगीर खान को दोपहर में सहाराहाट और आस-पास के इलाकों में ले जाया गया।

बंगाल में सरकार बदलते ही हेलमेट की बिक्री में आई तेजी

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। बड़ी बात यह कि हाल के समय में हेलमेट्स की बिक्री में काफी तेजी देखी जा रही है। 4 मई को आए चुनाव नतीजों ने राज्य के हालात बदल दिए। नई बीजेपी सरकार के कार्यभार संभालने से पहले ही पुलिस ने समाज के सभी वर्गों और इलाकों में हेलमेट नियमों के उल्लंघन पर सख्ती शुरू कर दी। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर सड़कों के साथ-साथ हेलमेट्स के शोरूम्स पर भी साफ दिखाई दे रहा है।इससे पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि ट्रैफिक के नियमों को लागू करने में भेदभाव हो रहा है। वे इस बात से नाराज थे कि कुछ लोगों को छूट दी जा रही थी जबकि दूसरों के साथ सख्ती की जा रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक झटके में स्थिति बदल दी है। हेलमेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक स्टड्स एक्सेसरीज की मई में पश्चिम बंगाल में बिक्री 70 फीसदी बढ़ गई। खास बात यह है कि बच्चों के हेलमेट की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। हेलमेट बनाने वाली एक और कंपनी वेगा हेलमेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि राज्य में मई से बिक्री में 30 फीसदी तेजी आई है। कंपनी के डायरेक्टर कुणाल चंडक ने बताया कि छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा मांग दिख रही है। इस मामले में कोलकाता में हेलमेट बेचने वाले करीब एक दर्जन दुकानदारों से बात की गई। उन्होंने मई में बिक्री में 40-60 फीसदी तेजी की पुष्टि की जबकि पहले यह बढ़ोतरी 8-9 फीसदी के आसपास रहती थी। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार केवल कोलकाता में ही मई में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 35,600 से ज्यादा चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि अगर आसपास के जिलों को मिला लिया जाए तो यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। स्टड्स एक्सेसरीज़ के जनरल मैनेजर (सेल्स एंड मार्केटिंग) आदित्य वर्मा ने कहा कि कस्बों और ग्रामीण इलाकों में कई लोग पहली बार हेलमेट खरीद रहे हैं। इसलिए डिमांड बढ़ी है। महानगर में हेलमेट की बिक्री में तेजी के आंकड़े हेलमेट नहीं पहनने पर कोलकाता में 35,657 लोगों का चालान मई में पश्चिम बंगाल में हेलमेट्स की बिक्री में 70 फीसदी उछाल बच्चों के हेलमेट्स की बिक्री में मई में देखी गई 100 फीसदी तेजी विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हर हफ्ते बढ़ रही तेजी गांवों और कस्बों में काफी डिमांड, कई लोग पहली बार खरीद रहेबच्चों के हेलमेट में तेजी की वजह यह है कि पूरे राज्य में अब हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। स्टड्स की बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के हेलमेट की मांग पहले सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित थी। लेकिन अब मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीपुर, कृष्णानगर,आसनसोल, बर्दवान, बांकुड़ा, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जैसे शहरों और कस्बों से भी डिमांड आ रही है। बीजेपी सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने को प्राथमिकता दी है। राज्य के कैबिनेट मंत्री अशोक कीर्तनिया ने बताया कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि हेलमेट न पहनने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें केवल सिखों को धार्मिक कारणों से छूट दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कुछ जिलों की पुलिस ने सुरक्षा का संदेश देने के लिए यमराज के वेश में जवानों को तैनात किया है।

कमजोर होती तृणमूल का वोट हासिल करने को मैदान में उतरी सीपीएम

निज संवाददाता : विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी के हार के बाद तृणमूल कांग्रेस टूटने के कगार पर पहुंच गई है। पूर्व सत्ताधारी पार्टी के टूटने से विपक्ष में एक खालीपन आ गया है। इस खालीपन को भरने की ज़रूरत है। पार्टी में लोगों का भरोसा फिर से जगाने की ज़रूरत है। इसलिए, सीपीएम ने जिला स्तर पर पार्टी कमेटियों को को पूरे राज्य में लगातार आंदोलन की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत हॉकरों के साथ खड़े होने के अलावा, चीज़ों की बढ़ती कीमतों यानी महंगाई और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के ख़िलाफ़ आंदोलन करने का निर्देश दिया गया है। 23 और 24 जून को सीपीएम की राज्य कमेटी की बैठक में चुनाव समीक्षा के साथ-साथ आंदोलन की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीपीएम को एक सीट मिली है। वाममोर्चा गठबंधन के उम्मीदवार ने भी एक सीट जीती है। आने वाले दिनों में इस संख्या को बढ़ाने के लिए, सीपीएम ने संगठन को मज़बूत करने और आंदोलन में कूदने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़िलों ने पहले ही बूथ-आधारित रिव्यू शुरू कर दिया है। ज़िले के प्रतिनिधि अगली राज्य कमेटी की बैठक में अलीमुद्दीन कोसमीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्य

अलीमुद्दीन स्ट्रीट में आंदोलन की तैयारी

कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि बूथ-आधारित समीक्षा में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, बीजेपी का दावा है कि उसे सभी हिंदुओं के वोट मिले हैं, लेकिन यह सही जानकारी नहीं है। हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। इसका ज़्यादातर हिस्सा तृणमूल को गया। कुछ सीपीएम को। तृणमूल अब कमज़ोर हो रही है। अल्पसंख्यकों के साथ-साथ हिंदू वोटों के इस हिस्से का समर्थन पार्टी की तरफ वापस लाने के लिए समय पर प्रोग्राम करने होंगे। साथ ही, अगर अल्पसंख्यक वोटों को गंभीरता से लिया जाए, तो भविष्य में पार्टी का जन समर्थन फिर से पाना मुश्किल नहीं होगा। सीपीएम राज्य कमेटी के सदस्य ने कहा कि इस मामले पर स्टेट कमेटी की बैठक में चर्चा होगी।

दूसरी तरफ, सीपीएम के 15 साल राज्य की सत्ता से बाहर रहने के बाद भी बूथ आधारित संगठन को मज़बूत नहीं किया जा सका। इसलिए, बैठक में ब्रांच लेवल पर संगठन को फिर से बनाने और कार्यकर्ता और समर्थक को सक्रिय रखने के लिए सही प्रोग्राम करने पर ज़ोर दिया जाएगा। खासकर बेरोज़गारी, किसानों की फ़सलों के दाम, मज़दूरों के हक़, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने पर भी जोर दिया जाएगा। सीपीएम नेतृत्व का मानना है कि सिर्फ़ बयान जारी करके बड़े आंदोलनों के ज़रिए लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होगा। फिर से, संगठन में नई पीढ़ी को शामिल करना और छात्र-युवा आंदोलन को बढ़ाना होगा। राज्य समिति सदस्य ने कहा कि पार्टी की चर्चा में युवा सदस्यता बढ़ाने की ज़रूरत और रणनीति पर चर्चा होगी।

महिला सशक्तिकरण पर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक कल्याण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, 7 जून रविवार को बंगनारी शक्ति के तत्वावधान में बेहाला के रायबहादुर रोड स्थित रायनगर मैदान के नजदीक एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में गायत्री पूजन, भारत माता पूजन, दीप प्रज्वलन, आरती तथा भक्तिमय नाम-संकीर्तन के माध्यम से एक पवित्र वातावरण का निर्माण हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों की मातृशक्तियों तथा विशिष्ट महिलाओं ने भाग लिया। विशेष अतिथियों के रूप में समाजसेवी चिकित्सक डॉ. अर्चना मजूमदार, पूर्व बेहाला के विधायक शंकर सिकदर तथा प्रसिद्ध नृत्यांगना संचिता भट्टाचार्य उपस्थित थीं। इसके अतिरिक्त बंगनारी शक्ति की सदस्याओं एवं क्षेत्र की अनेक महिलाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण की कामना को अभिव्यक्त करना था। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक एवं सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही महिला समाज आज एक नई आशा का उदय देख रही है। इसी आशा का स्वागत करते हुए तथा समस्त समाज के कल्याण की कामना से इस गायत्री पूजन, भारत माता पूजन एवं दीपयज्ञ का आयोजन किया गया। नाम-संकीर्तन की मधुर ध्वनि, सैकड़ों दीपों की ज्योति तथा सामूहिक आरती के बीच पूरा आयोजन स्थल एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण से आलोकित हो उठा। अंत में सामूहिक स्वर में 'वंदे मातरम' के गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस आयोजन ने उपस्थित सभी लोगों के मन में नई आशा, एकता और समाज कल्याण का सकारात्मक संदेश पहुंचाया। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी बंगनारी शक्ति की महिला समन्वय संयोजिका (दक्षिण बंग) नीलांजना राय ने दी।

नेताओं की वर्दी में छिपी 105 साल पुरानी सियासी दास्तान

गांधी-नेहरू से शुरू हुआ खेल

निज संवाददाता : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सूट-बूट वाली तस्वीर ने इन दिनों सियासत में भूचाल ला दिया है। एक सरकारी कार्यक्रम में विजय जब सूट-बूट में नजर आए तो डीएमके और एआईएडीएमके समेत कई दलों ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना था कि तमिल संस्कृति और द्रविड़ आंदोलन की पहचान रहे पारंपरिक लिबास को छोड़कर एक तमिल मुख्यमंत्री का पूरे विदेशी अंदाज में आना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सवाल सिर्फ एक सूट का नहीं है, यह पूरी बहस हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि भारत में नेताओं की पोशाक कभी भी मामूली कपड़ा नहीं रही, बल्कि विचारधारा, क्षेत्रीय अस्मिता और सियासत की पहचान रही है।

तमिलनाडु की राजनीति में कपड़े हमेशा एक गहरा संदेश देते हैं। पेरियार से लेकर अन्नादुरै, करुणानिधि, एमजीआर और जयललिता तक, लगभग हर बड़ा नेता सफेद वेष्टी-शर्ट या फिर साड़ी में नजर आया, जो सादगी और तमिल गौरव का प्रतीक बन गया। द्रविड़ आंदोलन ने शुरू से ही उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी छवि के खिलाफ मोर्चा खोला और इसमें पहनावा भी एक बड़ा हथियार था। ऐसे में जब मुख्यमंत्री विजय, जो खुद को आम तमिल का प्रतिनिधि बताते हैं, एक सरकारी कार्यक्रम में फुल सूट पहनकर पहुंचे तो विपक्षी दलों को मानो मुद्दा हाथ लग गया।डीएमके नेताओं ने इसे दिल्ली की गुलामी तक कह डाला, जबकि अन्नाद्रमुक ने सवाल उठाया कि क्या विजय को तमिल परंपरा से शर्म आती है। सोशल मीडिया पर भी यह बहस छिड़ गई कि आखिर भारतीय नेता कोट-पैंट से इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हैं और कुर्ता-पायजामा उनकी मजबूरी है या रणनीति? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें करीब 105 साल (1921) पीछे जाना होगा, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तब तक कांग्रेस के बड़े नेता भी कोट-पतलून और टाई लगाकर अंग्रेजों से बहस करते थे। महात्मा गांधी ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। जब वे विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और स्वदेशी की बात करने लगे, तो उन्होंने खुद मिल में बुनी खादी की धोती और साधारण कुरता अपनाया। यह सिर्फ एक पोशाक नहीं थी, यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आम भारतीय से जुड़ने का सबसे मजबूत संदेश थी। 1925 में 'यंग इंडिया' में लिखते हुए गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा था-खादी मेरे लिए स्वराज की सांस है। जो आदमी खादी नहीं पहनता, वह भारत की गरीबी को नहीं समझ सकता। इसके ठीक बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देसी और विदेशी का एक नायाब मिक्स तैयार किया। वे चुस्त चूड़ीदार पायजामे के साथ लंबा अचकन या बंद गले का कोट पहनते थे, जिसे दुनिया ने 'नेहरू जैकेट' का नाम दिया। उनके सीने पर लाल गुलाब और सिर पर गांधी टोपी ने ऐसी छवि खड़ी की कि आधुनिक भारत का एक स्टाइलिश लेकिन नॉन-वेस्टर्न नेता उभरकर सामने आया। यह जैकेट इस बात का सबूत थी कि हम पश्चिम से सीख सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। धीरे-धीरे कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट हर उस नेता की पहली पसंद बन गए, जो जनता के बीच जाना चाहता था और खुद को अंग्रेजों या बाद में बड़े उद्योगपतियों से अलग दिखाना चाहता था।अब असल सवाल यह है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नेता कोट-पतलून या जींस-टीशर्ट में क्यों नहीं दिखते, जबकि देश का हर दूसरा नागरिक यह सब पहनता है? इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं।

पहली वजह : कुर्ता-पायजामा अब एक राजनीतिक 'यूनिफॉर्म' बन चुका है जो किसी भी नेता को तुरंत स्थानीय और जमीनी दिखाता है। सूट पहनकर निकलने वाला नेता एलीट यानी कुलीन वर्ग से जुड़ा माना जाता है, जबकि ढीला-ढाला खादी का कुर्ता पहनने वाला नेता अपने आप आम आदमी की तरह दिखता है।

दूसरी वजह : हमारे देश की गर्मी और उमस में सूट-टाई पहनकर जनसभा करना किसी सजा से कम नहीं है, जबकि सूती कुर्ता हवादार और आरामदायक रहता है।

तीसरी वजहः पंजाब का नेता हो या बंगाल का, सबके कुर्ते की कटाई और साथ में पहने जाने वाले स्टोल या शॉल में फर्क होता है, जो उसकी स्थानीय जड़ों को दिखाता है। तमिलनाडु में तो सफेद वेष्टी और शर्ट इतनी मजबूत सियासी पहचान है कि वहां किसी नेता का सूट पहनना अपने वोटरों को खुद से दूर करने जैसा हो सकता है, ठीक वैसा ही जैसा विजय के मामले में होता दिख रहा है। असल में, हर नेता की अलमारी एक रणनीति के तहत तय होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे अच्छे मौजूदा उदाहरण हैं। वे देश में तो हमेशा हाफ स्लीव या फुल स्लीव कुर्ता और चूड़ीदार पहनते हैं, ऊपर से स्टाइलिश सदरी जैकेट डाल लेते हैं, लेकिन विदेश दौरे पर कभी-कभी बंदगला सूट भी पहन लेते हैं। दोनों ही परिधानों से वे अपनी छवि को साधते हैं यानी अंदर देसी और बाहर वैश्विक। ठीक इसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी सफेद कुर्ता-पायजामा और कभी-कभी जींस-टीशर्ट में भी दिख जाते हैं, जो नौजवानों को जोड़ने का प्रयास है। लेकिन सूट का इस्तेमाल चुनिंदा मौकों पर ही होता है, जैसे संसद में शपथ ग्रहण या किसी बहुत ऊंचे राजनयिक डिनर में। अगर कोई नेता लगातार सूट में घूमने लगे तो जनता उसे अपने बीच का नहीं मानती। विजय की इस कंट्रोवर्सी के बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारतीय नेताओं को अपनी पोशाक की सियासी कंडीशनिंग से बाहर निकलना चाहिए।

कुछ युवा विधायक आजकल जींस-शर्ट और जैकेट में दिखने लगे हैं, जो बताता है कि बदलाव की बयार चल रही है। लेकिन द्रविड़ पार्टियों की तीखी प्रतिक्रिया यह भी साफ करती है कि कपड़ों का राजनीति से रिश्ता जल्दी टूटने वाला नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्य में तो वेष्टी का प्रतीकात्मक महत्व इतना गहरा है कि सूट पहनने को आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। हो सकता है, विजय अपनी अगली जनसभा में फिर से वेष्टी-शर्ट में ही नजर आएं, ताकि यह संदेश जाए कि उन्होंने जनता की भावना को समझा है। कुल मिलाकर, कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट की यह यात्रा गांधी की खादी से शुरू होकर नेहरू के आधुनिक भारत के सपने और फिर हर राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता तक पहुंची है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे यहां नेता सिर्फ अपने भाषणों से नहीं, बल्कि अपने पहनावे से भी बहुत कुछ कह जाता है। विजय के सूट का बवाल इसी पुरानी लेकिन मजबूत हो चुकी परंपरा का ताजा अध्याय है।

कुल मिलाकर, कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट की यह यात्रा गांधी की खादी से शुरू होकर नेहरू के आधुनिक भारत के सपने और फिर हर राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता तक पहुंची है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे यहां नेता सिर्फ अपने भाषणों से नहीं, बल्कि अपने पहनावे से भी बहुत कुछ कह जाता है। विजय के सूट का बवाल इसी पुरानी लेकिन मजबूत हो चुकी परंपरा का ताजा अध्याय है।

बंगाल में भी लागू होगी केंद्र की नई शिक्षा नीति

नए शिक्षा मंत्री ने दिया संकेत

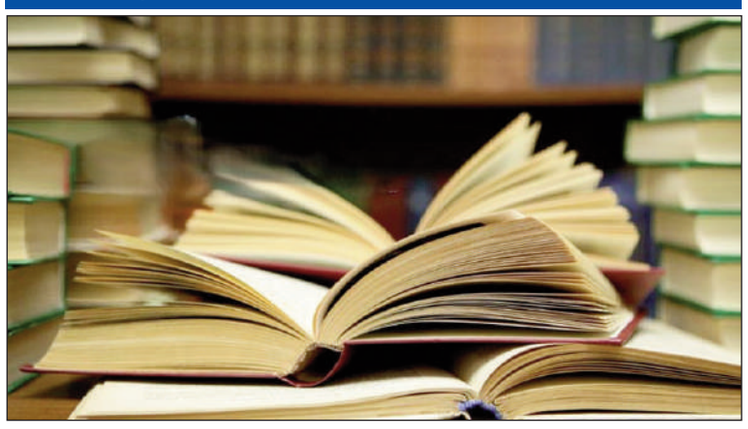

निज संवाददाता : बंगाल के नए उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बुधवार को कहा कि उनका विभाग नरेंद्र मोदी सरकार की 2020 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) को पूरी तरह से लागू करेगा।उनके इस दावे से कि राज्य इस पॉलिसी का सख्ती से पालन करेगा, तुरंत ''इंडियन नॉलेज सिस्टम'' पर आधारित करिकुलम शुरू करने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई। यह एनईपी का एक ऐसा पहलू है जिसका पिछली ममता बनर्जी सरकार ने विरोध किया था। राज्य प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए दिल्ली में अपनाए जाने वाले सिस्टम की तरह एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट शुरू करने का रास्ता भी बन सकता है।

मंत्री ने कहा-नई सरकार पिछले 50 सालों में नए उच्च शिक्षा में आई गिरावट को रोकने की कोशिश करेगी। वाममोर्चा के दौर में, नए उच्च शिक्षा को औसत दर्जे को बढ़ावा देने से नुकसान हुआ। पिछले 15 सालों में, इस सेक्टर से मेरिट काफी हद तक गायब रही है। उन्होंने कहा-हमारा काम इस गिरावट को उलटना और राज्य में नए उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड को वापस लाना है। शिक्षा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए चट्टोपाध्याय ने कहा कि बंगाल कभी इंडियन नॉलेज सिस्टम में ''एक पोलस्टार'' था, और इस ''खोए हुए गर्व'' को वापस पाना होगा। ''हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हूबहू फॉलो करेंगे। राज्य उस रास्ते से अलग नहीं होगा जो सेंटर बनाएगा.... बंगाल कभी भारतीय ज्ञान प्रणाली में पोलस्टार था। हमें खोया हुआ गर्व वापस पाना है। चट्टोपाध्याय ने कहा-हमारा मकसद उच्च शिक्षा में एक्सीलेंस और स्किल की खोज को फिर से शुरू करना है, यही बीजेपी सरकार का मकसद होगा। पिछले 15 सालों में बंगाल ने लगातार खुद को देश से अलग करने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा विभाग का पहला काम बंगाल को देश के साथ जोड़ना होगा। मंत्री ने कहा-यह शिक्षा के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करना में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) इंडियन नॉलेज सिस्टम (आईकेएस) जिसमें जनजातीय अभ्यास, शास्त्रीय विज्ञान, वैदिक गणित और पारंपरिक चिकित्सा शामिल हैं को स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक बहु-विषयक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का आदेश देती है। चट्टोपाध्याय ने कहा कि वह ''यह पक्का करने की कोशिश करेंगे कि बंगाल को डबल-इंजन सरकार होने का फायदा मिले'' राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी सरकार हो। विधान चंद्र रॉय आखिरी मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल (जनवरी 1948 से जुलाई 1962) में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया। बाद में, सिद्धार्थ शंकर रे (मार्च 1972 से अप्रैल 1977) के कार्यकाल में, नक्सली आंदोलन से पैदा हुई गड़बड़ियों के कारण डबल-इंजन सरकार का फायदा नहीं मिल सका। अगले पांच दशक हमने केंद्र का विरोध करते हुए बिताए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा-पांच दशकों के बाद, बंगाल के लिए डबल-इंजन सरकार के फायदे उठाने का मौका आया है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, केरल और तमिलनाडु ने कभी भी केंद्र की अनदेखी करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आगे कहा-बंगाल ने ऐसा किया, और इससे मंदी आई। हालांकि पिछली ममता बनर्जी सरकार ने एनईपी के कुछ फीचर्स लागू किए थे, जैसे चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना, लेकिन उसने इसे पूरी तरह लागू करने का विरोध किया था।

शिक्षाविदों के मुताबिक, विरोध का एक मुख्य कारण एनईपी का इंडियन नॉलेज सिस्टम पर ज़ोर देना था। ममता बनर्जी सरकार ने 2023 में एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी पेश की और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूएटी) का विरोध किया, जिसे एनईपी 2020 को लागू करने के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सीयूईटी को अपनाने से मना कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि एक जैसा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लोकल एकेडमिक स्टैंडर्ड को कमजोर कर सकता है और ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी कम कर सकता है।

होममेकर्स से राष्ट्र निर्माता तक

सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों के योगदान को माना

निज संवाददाता : भारत में करीब 211 मिलियन वयस्क औरतें हैं जिनका मुख्य काम घर का काम करना है। यानी जिन्हें हम हाउसवाइफ (गृहणियां) कहते हैं। इनके लिए हम होममेकर जैसा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। कई मामलों में, अपनी काबिलियत के बावजूद, कई शादी के बाद पारिवारिक कारणों से बाहर के काम में शामिल नहीं होती हैं, और हो भी नहीं सकतीं। कई ने परिवार बनाना को अपना लक्ष्य चुना है। एक भारतीय हाउसवाइफ औसतन 8 से 9 घंटे घर का काम करती है। हालांकि यह भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, फिर भी आर्थिक मूल्यांकन में इसे नज़रअंदाज़ किया जाता है। नतीजतन, उन्हें परिवार में कुछ तिरस्कार और अनदेखी सहनी पड़ती है। परिवार में काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा सम्मान और अधिकार मिलते हैं। पुरुष सदस्य भी समय-समय पर पैसे के मामलों में उन्हें टोकते रहते हैं। हालांकि हर कोई घुटन महसूस करता है जब एक दिन हाउसवाइफ का काम उनके कंधों पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी, हम इसे पहचानने में बहुत हिचकिचाते और झिझकते हैं। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 22,372 हाउसवाइफ ने आत्महत्या की। यानी हर दिन 61 हाउसवाइफ़ सुसाइड कर रही हैं। अनगिनत औरतें अपने पतियों की अनदेखी, टॉर्चर और नज़रअंदाज़ करने की वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उनके आने-जाने की आज़ादी पर कई तरह की रोक लगा दी जाती है। ज़िंदगी के एक पड़ाव पर, कोई सपना या उम्मीद नहीं रहती। नतीजतन, कई अपनी ज़िंदगी खत्म करने का फ़ैसला कर लेती हैं।इसी सिलसिले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में हाउसवाइफ़ को राष्ट्र निर्माता कहा है। एक रोड एक्सीडेंट केस में मुआवज़े का हिसाब लगाते हुए, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया है कि अगर किसी हाउसवाइफ़ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो घर और देखभाल की सेवाओं के नुकसान की वित्तीय मूल्य कम से कम 30,000 रुपये हर महीने मानी जाए। यानी, जहां पहले हाउसवाइफ़ के काम को अक्सर अकुशल श्रम या उससे भी कम कीमती श्रम माना जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उस सोच को पूरी तरह से खारिज़ कर दिया है। उसने उनके योगदान को पहचाना है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चे पालने, परिवार की देखभाल और घर के कामों के ज़रिए औरतें समाज और देश की आर्थिक बुनियाद में जो अनदेखा योगदान देती हैं, वह किसी भी तरह से कम नहीं है। ऐसी नीति किसी भी सभ्य देश में ज़रूरी है। फिर भी हमें समाज के 'आधे आसमान' को पीछे छोड़ते हुए खुद को 'प्रोग्रेसिव' का लेबल देने के बारे में दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या यह 'पितृसत्तात्मक' सोच सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बदल सकती है? अभी उस पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 'होममेकर्स' से 'राष्ट्र निर्माता' बनने का सफ़र मुश्किल नहीं होगा अगर समाज के सभी वर्ग सहमत हों और हिस्सा लें।

ताश के पत्तों की तरह बिखरती तृणमूल कांग्रेस

निज संवाददाता : बंगाल में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस तिल-तिल कर बिखर रही है। बीते 4 मई को बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार की विदाई का जनादेश सुनाया तब किसी ने भी सपने नहीं सोचा था कि इस हार के बाद तृणमूल कांग्रेस इतनी जल्दी बिखरने लगेगी। मालूम हो कि बंगाल विधानसभा में तृणमूल के 80 विधायक जीतकर आए थे जिनमें से पहले 58 विधायक अलग हुए फिर उनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई, नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने अपने मन का बना लिया। लोकसभा में 19 सांसदों ने बागी होकर अलग गुट बना लिया है, बागियों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। राज्यसभा सांसदों के त्यागपत्र भी आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुखेदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव तथा प्रकाश चिक बराईक इस्तीफा दे चुके हैं। आश्चर्यजनक रूप से ममता के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जिला और पंचायत स्तर पर भी पार्टी की यही स्थिति है।मात्र एक महीना पहले तक यही सांसद और विधायक ममता दीदी के साथ साए की तरह लगे रहते थे। जैसे ही बंगाल की जनता ने सत्ता बदली इन नेताओं का रुख बदल गया। आज ये नेता जिन विषयों पर ममता और अभिषेक बनर्जी को कोस रहे हैं सत्ता में रहते हुए कभी उन विषयों पर मुंह नहीं खोला, आर.जी. कर और संदेशखाली तक ये लोग मुंह में दही जमाए थे। राजनैतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई न कोई केस चल रहा है और सत्ता जाने के बाद ममता दीदी में इनको बचाने का सारथ्य नहीं रहे तो ये भविष्य में किसी जांच और सजा से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तृणमूल सांसदों व विधायकों की लगातार बगावत से यह संकेत भी जा रहा है कि क्या ममता दीदी का अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रति अधिक झुकाव उनकी पार्टी की इस हालत का कारण है। इससे तृणमूल के बागी नेताओं के स्वार्थी चरित्र की भी पोल खुल रही है। दल में तानाशाही इनको तब दिखाई दी जब सत्ता की मलाई छीन गई, यदि अभिषेक बनर्जी की अगुआई में पार्टी जीत गई होती और इनका लूट खसोट का धंधा चलता रहता तो इनकी आज जागी हुई आत्मा सोई पड़ी रहती। आज जो सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं उनमें से दस पहली बार चुनकर आए हैं। ये तृणमूल नेताओं की वो

पीढ़ी है जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नया चेहरा बनाकर आगे बढ़ाया था। अब यही लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए ममता दीदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं बंगाल में सत्ता में आई पार्टियाँ कम से कम डेढ़-दो दशक सत्ता में रहती हैं, इस तरह आने वाले 15-20 वर्षों तक इनका कोई भविष्य नहीं होगा। तृणमूल नेताओं के प्रति जनता के गुस्से का आलम ये है कि चुनाव में पार्टी को धूल चटाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा है। आए दिन तृणमूल नेताओं की सड़कों पिटाई की जा रही है। तृणमूल नेता जहां भी जाते हैं जनता उन्हें चोर-चोर कहकर पुकारती है और उन पर टमाटर-अंडे फेंकती है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओ तक पर अंडे टमाटर फेंके जा चुके हैं और पिटाई हो चुकी है। यह भी संभव कि बंगाल की जनता में व्याप्त इस भयंकर आक्रोश से बचने के लिए भी तृणमूल नेता बगावती हो रहे हों। तृणमूल के जिला स्तरीय नामचीन नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती, बिधान नगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती और कटवा म्युनिसिपलिटी चेयरमैन कमलकांता चक्रवर्ती ने सौ से अधिक पार्षदों सहित इस्तीफा दे दिया है। राज्यभर से तृणमूल से लगातार इस्तीफों व बगावत के समाचार आ रहे हैं। हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर व दक्षिण -24 परगना जैसे गढ़ों में प्रतिदिन पंचायत सदस्यों के पाला बदलने की ख़बरें आ रही हैं। टीएमसी में बगावत व इस्तीफों के बाद कोलकाता नगर निगम ही भंग कर दिया गया है। बंगाल में यह भी दावा किया जा रहा है कि इनमें से बहुत से लोग जेल जाने से बचने के लिए यह तरीका अपना रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल का कुख्यात चेहरा और चुनावों के दौरान अपने आप को पुष्पा कहने वाला फाल्टा विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार जहाँगीर खां के जेल जाने से अफरा तफरी का माहौल है। तृणमूल नेताओं के पाप जैसे उतरा रहे हैं। बंगाल पुलिस को संदेशखाली के तालाब से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, एक खेत से करोड़ों का कैश और हथियार मिले हैं। बमों व अन्य हथियारों की फैक्ट्रियां मिल रही हैं। हजारों की संख्या में सफ़ेद साड़ियाँ मिली हैं जो तृणमूल ने चार मई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की विधवाओं को देने के लिए रखी थीं यदि गलती से भी तृणमूल जीत जाती तो यही लोग जो आज इस्तीफा देकर भाग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के नर संहार का नेतृत्व करते। अपराधों की जो फेहरिस्त है उसे देखकर लगता है कि ममता दीदी और उनके चाटुकारों का शेष जीवन अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने या फिर जेल में ही बीतने वाला है। एक समय वाराणसी लोकसभा से पीएम नरेंद्र मोदी को हराने और दिल्ली आकर इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली ममता दीदी के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा कर रखना भी मुश्किल हो चुका है।

कोचिंग वॉर के चंगुल में फंसा ज्ञान का केंद्र, दांव पर मासूम छात्रों का भविष्य

निज संवाददाता : बिहार के पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका देश भर में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की उम्मीदों का केंद्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस इलाके से जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं, उसने न केवल शिक्षा के इस मंदिर को शर्मसार किया है बल्कि बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया है। जिन गलियों में सुबह से शाम तक किताबों के बंडल, पेन और कॉपियां दिखाई देती थीं, वहां अचानक पत्थरबाजी, लाठी-डंडे और हवाई फायरिंग की गूंज सुनाई देने लगी। यह विवाद महज दो कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के नाम पर चल रहे करोड़ों रुपये के उस बाजार का नग्न प्रदर्शन है, जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ भीड़ और वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है। इस तथाकथित कोचिंग वॉर ने यह साबित कर दिया है कि जब शिक्षा व्यवसाय बन जाती है, तो नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पतन किस कदर होता है। इस पूरे बवाल की शुरुआत बेहद मामूली और बचकानी वजह से हुई, जिसे जानकर किसी भी सभ्य समाज का सिर घोर निराशा से झुक जाएगा। बताया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान की ओर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 12 हजार छात्रों के सफल होने का दावा करते हुए बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। आरोप है कि यह पोस्टर प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के साइन बोर्ड के ऊपर या उसके बेहद करीब चिपका दिए गए। इसके बाद वर्चस्व की इस जंग में सीढ़ियां लगाकर बैनर फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। पोस्टर फाड़े जाने की इस छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक ऐसी आग का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके के सुरक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दो पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए, लाठियां चलीं, ईंट-पत्थरों की बौछार हुई और देखते ही देखते वह परिसर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया जहां हजारों छात्र अपने सुनहरे कल का सपना बुनने आते हैं। घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया के महारथी और लाखों युवाओं के आदर्श बने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने मीडिया के सामने आकर बेहद सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कैमरे के सामने पूरी गंभीरता से कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है और उन्होंने अपनी आंखों से एक-दो नहीं बल्कि आठ से

दस राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। एक शिक्षक के मुंह से इस तरह की बात सुनकर पूरे राज्य के अभिभावकों और छात्रों में दहशत फैल गई। लेकिन जब कानून के रक्षकों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और घटनास्थल के साथ-साथ आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, तो कहानी पूरी तरह पलट गई।

पुलिस की शुरुआती जांच में दूर-दूर तक गोली चलने या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा फायरिंग करने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके उलट, सीसीटीवी में यह साफ दिखाई दिया कि खान सर के अपने ही सुरक्षा गार्ड हवा में हथियार लहराते और हमला करते नजर आ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और खुद खान सर को भी देर रात लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक रात में अपनी आंखों से गोलियां बरसने की गवाही दे रहे थे, सुबह होते-होते उनके सुर पूरी तरह बदल गए। वे अपने ही दावों से यू-टर्न लेते हुए यह कहने लगे कि अब पुलिस की जांच के बाद ही असलियत का पता चलेगा या फिर जब उनका घायल गार्ड ठीक होकर आएगा तब वह सच बताएगा। एक शिक्षक के बयानों में ऐसा विरोधाभास और तथ्यों को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बेहद चिंताजनक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो केवल दिमाग में तथ्य ठूंसे, बल्कि वह है जो छात्र को सत्य की खोज के लिए तैयार करे। लेकिन आज के डिजिटल युग के इन तथाकथित गुरुओं के तथ्य और सत्य दोनों ही गंभीर संदेह के घेरे में आ गए हैं। इस विवाद का दूसरा पहलू और भी भयावह है। फैजल खान की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को फौरन गिरफ्तार कर लिया।

रौशन आनंद बिहार के एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। रौशन आनंद के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप है कि खान सर ने राजनीतिक और व्यावसायिक रंजिश के तहत उनके गुरु पर झूठे आरोप लगाए हैं। सोचिए, जिन नौजवानों को इस वक्त कमरों में बंद होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वे अपने-अपने पसंदीदा शिक्षकों के अंधविश्वास में सड़कों पर नारेबाज़ी कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने पर आमादा हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज के ये मशहूर यूट्यूब शिक्षक बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए एक ट्रोल आर्मी और हिंसक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं।यह पहली बार नहीं है जब पटना की धरती पर कोचिंग संचालकों के कारण इस तरह का उपद्रव हुआ हो। इतिहास गवाह है कि साल 2019 में भी इसी मुसल्लहपुर इलाके में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हुई थी। उस वक्त भी दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन दुकानदारों के हौसले बुलंद रहे। इस साल भी सरस्वती पूजा के मौके पर इसी तरह के हिंसक टकराव की खबरें आई थीं। अगर समय रहते पुलिस और प्रशासन ने इन व्यावसायिक संस्थानों पर नकेल कसी होती, तो आज यह नौबत नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों में इसलिए मोटी फीस देकर भेजते हैं कि वे वहां से लहूलुहान होकर लौटें? अगर यह पत्थरबाजी दिन के वक्त होती, जब हजारों छात्र क्लास में मौजूद होते हैं, और किसी मासूम के सिर पर वह पत्थर लग जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या ये शिक्षक अपनी अकूत संपत्ति और टीआरपी के नशे में किसी बच्चे की जान की कीमत चुका पाते?इस पूरे खेल का सबसे कड़वा सच आर्थिक हितों का टकराव है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि कुछ शिक्षक बहुत कम पैसे में समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर की तुलना की जाती है, तो असलियत कुछ और ही निकलती है। जहां दो साल के ऑफलाइन कोर्स के लिए एक संस्थान किस्तों में दस हजार रुपये लेता है, वहीं दूसरा संस्थान एकमुश्त बीस हजार रुपये वसूलता है। ऑनलाइन कोर्सेस में भी फीस का अंतर जमीन-आसमान का है। जाहिर है, यह पूरी लड़ाई किसी शिक्षा सुधार या गरीब बच्चों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह अधिक से अधिक छात्रों को अपनी ओर खींचने और करोड़ों रुपये का टर्नओवर खड़ा करने की कॉरपोरेट जंग है।अब इस मामले ने पूरी तरह से कानूनी मोड़ ले लिया है। पटना पुलिस ने कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रामक जानकारी फैलाने की संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने बड़ी ही चतुराई से बयान दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और उनके गार्डों ने जो कुछ भी किया, वह आत्मरक्षा में किया था। वे कानून का सम्मान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अतीत में उनका रिकॉर्ड कुछ और ही बयां करता है। चाहे वह रेलवे परीक्षा के दौरान छात्रों को उग्र आंदोलन के लिए भड़काना हो, बीपीएससी परीक्षा के समय अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो या फिर हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में एनकाउंटर जैसे उत्तेजक बयान देकर माहौल खराब करना हो, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। जब कोई मुख्यधारा का माध्यम इन कोचिंग संस्थानों की इस खतरनाक कार्यप्रणाली और उनके गिरते स्तर पर सवाल उठाता है, तो ये यूट्यूब शिक्षक अपने लाखों फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके डिजिटल लिंचिंग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की एक फौज छोड़ दी जाती है, जो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर गाली-गलौज पर उतर आती है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम जैसी विदेशी एनजीओ की रैंकिंग का हवाला देकर देश की पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि वे खुद यह भूल जाते हैं कि वे शिक्षा के नाम पर कौन सा अनैतिक धंधा चला रहे हैं। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। पटना की इस घटना ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के इन आधुनिक कुरुक्षेत्रों में अब ज्ञान की नहीं, बल्कि बंदूकों और पत्थरों की भाषा बोली जा रही है। सरकार और प्रशासन को अब बिना किसी दबाव के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो मिसाल बन सके, ताकि बिहार का कोई और होनहार छात्र इस गंदे व्यावसायिक खेल की बलि न चढ़े।

किराया माफ़ी के बाद सरकारी बसों में बढ़ी महिला यात्रियों की संख्या

- सरकारी बसों में 14 फीसदी महिला यात्री बढ़ी
- कोलकाता और उसके उपनगरों में हर दिन लगभग 2 लाख यात्री सरकारी बसों में सफर करते हैं

निज संवाददाता : एक जून से सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करने लगी हैं। यह सुविधा एसी और नॉन एसी सभी तरह की बसों में उपलब्ध है। उसके बाद के आंकड़े कहते हैं कि सरकारी बसों में 14 फीसदी महिला यात्री बढ़ी हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, जहां पहले महिला यात्री सरकारी बसों में सफर करती थीं, वहीं अब यह बढ़कर 56 फीसदी हो गई है। इस अतिरिक्त 14 फीसदी की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरकारी एसी बसों में हुई है। जो लोग पहले कभी एसी बसों में सफर नहीं करते थे, वे अब इन बसों में सफर कर रही हैं। एक शब्द में कहें तो सरकार के इस फैसले से महिलाएं काफी खुश हैं। कैसी चल रही है यह सेवा? बस में सवार हर महिला यात्री को जीरो बैलेंस टिकट दिया जा रहा है। हालांकि, कंडक्टर यात्री से यह पता कर रहा है कि वे कहां जा रही हैं और उस दूरी के आधार पर जीरो डॉलर का टिकट जारी कर रहा है। परिवहन विभाग ने अभी यह नहीं बताया है कि इन सात दिनों में महिला यात्रियों को कितने टिकट जारी किए गए हैं। नवान्न सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने महिलाओं की मुफ्त यात्रा की लागत के लिए पहले ही पांच निगमों को 12.5 करोड़ रुपये दिए हैं। इसे खर्च करने के बाद, नवान्न फिर से हर महीने महिलाओं के लिए बस किराए का खर्च कॉर्पोरेशन को देगा। यह पैसा सीएसटीसी, सीटीसी, डब्ल्यूबीएसटीसी, एसबीएसटीसी और एनबीएसटीसी को दिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस सर्विस के शुरू होने से पहले किए गए सर्वे से पता चलता है कि कोलकाता और उसके उपनगरों में हर दिन 1 लाख 80 हजार से 2 लाख यात्री सरकारी बसों में सफर करते हैं। यानी, कैलकुलेशन के हिसाब से 1,250 यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है। हर ट्रिप में एसी और नॉन-एसी मिलाकर अब करीब 600 बसें सड़क पर हैं।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.बटरफ्लाई, 2. कथा, 3.शेफाली वर्मा, 4. एम्स्टर्डम, 5. कर्नाटक

हकीकत में बदलने लगा है राहुल गांधी का 20 साल पुराना सपना

कांग्रेस में 'ओल्ड गार्ड' की जगह अब 'न्यू जेनरेशन' राज

संजय सक्सेना

भारतीय राजनीति के सबसे पुराने दल कांग्रेस के भीतर इन दिनों एक खामोश लेकिन बेहद गहरा बदलाव आकार ले रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे दो दशकों की एक लंबी राजनीतिक तपस्या और जिद छिपी है। साल 2004 में जब राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था, तब से उनका एक सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कांग्रेस का सांगठनिक कायाकल्प और जनरेशन चेंज यानी पीढ़ीगत बदलाव। वह कांग्रेस को पार्टी के उन बुजुर्ग और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के चंगुल से बाहर निकालना चाहते थे, जो सिर्फ बंद कमरों में नीतियां बनाते थे। राहुल का सपना एक ऐसी युवा, आक्रामक और जमीन पर चौबीसों घंटे लड़ने वाली पार्टी तैयार करना था, जो सीधे जनता के बीच खड़ी दिखे। शुरुआती दौर में राहुल गांधी का यह सियासी प्रयोग पुराने दिग्गजों (ओल्ड गार्ड) के कड़े विरोध, अंदरूनी खींचतान और सोनिया गांधी के दरबार में बुजुर्ग नेताओं के वीटो पावर के चलते परवान नहीं चढ़ सका था। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के भीतर जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी का 20 साल पुराना यह सपना अब हकीकत में बदलने लगा है। इस पीढ़ीगत बदलाव की सबसे ताजा और दमदार बानगी हालिया राज्यसभा चुनावों के टिकट वितरण में देखने को मिली है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें पुराने और पारंपरिक चेहरों को दरकिनार कर पूरी तरह संगठन और राहुल गांधी के करीबियों पर भरोसा जताया गया है। कर्नाटक से स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। ये सभी नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इन्हें राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माना जाता है। प्रवीण चक्रवर्ती को राहुल का बेहद करीबी रणनीतिकार माना जाता है, जो पार्टी के प्रोफेशनल कांग्रेस और डेटा विभाग के प्रमुख के तौर पर आर्थिक व तकनीकी मामलों को देखते हैं। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस का

गठबंधन कराने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही थी। इसी तरह, राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय का कामकाज संभालते हैं, जबकि पवन खेड़ा अपनी मुखर आवाज से टीवी डिबेट्स में सरकार को फ्रंटफुट पर घेरने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को कर्नाटक जैसी सुरक्षित सीट से उच्च सदन भेजकर पूरे कैडर को एक साफ संदेश दिया है कि जो जमीन पर लड़ेगा, उसे उसका हक और इनाम जरूर मिलेगा।यह बदलाव सिर्फ दिल्ली के गलियारों या राज्यसभा के टिकटों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों की सत्ता और कमान सौंपने में भी राहुल गांधी की पसंद साफ दिखाई दे रही है। केरल में कांग्रेस ने 69 साल के रमेश चैन्नितला और 64 साल के केसी वेणुगोपाल जैसे कद्दावर नेताओं को नजरअंदाज कर 61 साल के वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इतना ही नहीं, केरल की नई सरकार के मंत्रिमंडल में 50 फीसदी मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम रखकर युवाओं को तरजीह दी गई। इसी तरह का एक बड़ा और साहसिक प्रयोग कर्नाटक में देखने को मिला। वहां 77 साल के सिद्धारमैया की जगह 64 साल के आक्रामक और संकटमोचक नेता डीके शिवकुमार की ताजपोशी की गई। कर्नाटक जैसे राज्य में जहां सामाजिक और जातीय समीकरण बेहद जटिल हैं, वहां नेतृत्व परिवर्तन करना एक बड़ी चुनौती थी। सिद्धारमैया ओबीसी (कुरुबा) समुदाय से आते हैं, जिन्हें नाराज करने का जोखिम कोई दल नहीं उठाना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से ताकतवर वोक्कालिगा जाति के डीके शिवकुमार पर दांव लगाया और संतुलन बनाए रखने के लिए ओबीसी समुदाय से आने वाले जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम और बीके हरिप्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। साथ ही, कैबिनेट में मल्लिकार्जुन खरगे और सिद्धारमैया के बेटों को जगह देकर भविष्य की लीडरशिप की राह भी खोल दी गई। इसी फेहरिस्त में तेलंगाना की कमान 56 साल के युवा और ऊर्जावान नेता रेवंत रेड्डी को सौंपना और हिमाचल प्रदेश में 62 साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाना यह साबित करता है कि अब राज्यों में ओल्ड गार्ड को राष्ट्रीय भूमिकाओं में भेजकर नई पीढ़ी को आगे किया जा रहा है।देखा जाए तो कांग्रेस में यह जेनरेशनल शिफ्ट करीब दो दशक बाद देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले जब बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव के तहत नेतृत्व में नए चेहरे सामने आए थे, तब कांग्रेस के बुजुर्ग नेतृत्व को लेकर काफी आलोचनाएं होती थीं। लेकिन अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक सीमाओं के भीतर रहते हुए इस ढर्रे को पूरी तरह बदल चुकी है। पहले राज्यों के बड़े फैसले वहां के क्षत्रप लिया करते थे, लेकिन अब हाईकमान ने संगठन के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रादेशिक और जिला संगठनों में राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस वाली मूल टीम के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सैयद नसीर हुसैन को जम्मू-कश्मीर, कृष्ण अल्लावरु को बिहार और सप्तगिरी उलाका जैसे युवा चेहरों को अहम राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में कमान 48 साल के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के हाथों में है, बिहार में 56 साल के राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में अजय राय और महाराष्ट्र में 58 साल के हर्षवर्धन सपकाल जैसे जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। इन तमाम नियुक्तियों से राजस्थान में सचिन पायलट समेत अन्य राज्यों के उन युवा नेताओं की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे के अध्यक्ष बनने और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होकर उभरने के बाद पार्टी में चाटुकारिता और परिक्रमा की राजनीति खत्म हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर संघर्ष करती दिखने लगी है, जो कि राहुल गांधी के इसी नए प्रयोग और दूरगामी विजन का नतीजा है।

अजब-गजब

प्रयोगशाला में पैदा किया जिंदा चूजे

वैज्ञानिकों ने किया दावा

निज संवाददाता : बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम माहौल तैयार कर जिंदा चूजों को जन्म देने में सफलता हासिल करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के इस दावे ने सभी को चौका दिया है। वैज्ञानिकों ने इस काम के लिए थ्री-डी प्रिंटेड तकनीक से तैयार किए गए एक खास ढांचे का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल असली अंडे के छिलके की तरह काम करता है। कंपनी का कहना है कि इस अनोखी तकनीक के जरिए अब तक 26 चूजों का जन्म हो चुका है। इनमें कुछ चूजे कुछ दिन के हैं, जबकि कुछ कई महीने तक जीवित रह चुके हैं। कंपनी के अनुसार इस प्रयोग में निषेचित मुर्गी के अंडों को एक विशेष कृत्रिम प्रणाली में रखा गया। इसके बाद पूरे सिस्टम को नियंत्रित तापमान वाले इनक्यूबेटर में सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम छिलके के भीतर एक खास झिल्ली लगाई, जो असली अंडे की तरह भ्रूण तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा चूजों के विकास के लिए अलग से कैल्शियम भी उपलब्ध कराया गया। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक भ्रूण के विकास को वास्तविक समय में देख और समझ पा रहे थे। कोलोसल बायोसाइंसेस लंबे समय से विलुप्त हो चुके जीवों को दोबारा धरती पर लाने की परियोजनाओं पर काम कर रही है।कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेन लैम का कहना है कि इस आर्टिफिशियल एग तकनीक का उपयोग भविष्य में न्यूजीलैंड के विलुप्त विशालकाय ''साउथ आइलैंड जायंट मोआ'' पक्षी को वापस लाने में किया जा सकता है। बताया जाता है कि मोआ पक्षी का अंडा सामान्य मुर्गी के अंडे से करीब 80 गुना बड़ा होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी बड़ी प्रजाति के लिए प्राकृतिक तरीके से अंडा तैयार करना वर्तमान समय में संभव नहीं है। हालांकि कंपनी के इस दावे पर कई स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने सवाल भी उठाए हैं। यूनिवर्सिटी एट बफेलो के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट विंसेंट लिंच का कहना है कि वैज्ञानिकों ने केवल कृत्रिम छिलका बनाया है, पूरा अंडा नहीं। उनके अनुसार असली अंडे में कई अस्थायी अंग और जैविक संरचनाएं होती हैं, जो भ्रूण को पोषण देने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करती हैं। इस कृत्रिम प्रणाली में वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं मौजूद नहीं थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफिल्ड की वैज्ञानिक निकोला हेमिंग्स ने भी कहा कि कृत्रिम छिलकों के जरिए चूजों का विकास पूरी तरह नई तकनीक नहीं है। इससे पहले भी प्लास्टिक आधारित कृत्रिम संरचनाओं में चूजों को विकसित करने के प्रयोग किए जा चुके हैं। उनका मानना है कि विलुप्त जीवों को वापस लाने की बजाय वैज्ञानिकों को मौजूदा संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस बीच न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बायोएथिसिस्ट आर्थर कैपलन ने इस तकनीक से जुड़े नैतिक और पर्यावरणीय सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि वैज्ञानिक किसी विलुप्त जीव को दोबारा बना भी लेते हैं, तो आज के बदले हुए पर्यावरण में उसका जीवित रहना बेहद कठिन होगा।

अमेजन के जंगलों में इस जनजाति की महिलाएं जानवरों के बच्चों को कराती हैं स्तनपान!

निज संवाददाता : दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जिनका जीवन जंगल, जानवरों और प्रकृति के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ब्राजील के अमेजन जंगलों में रहने वाली 'आवा जनजाति' भी अपने अनोखे जीवन और जानवरों के प्रति मातृत्व भाव के कारण चर्चा में रहती है। इस जनजाति की महिलाएं अनाथ जंगली जानवरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं और उन्हें स्तनपान तक कराती हैं। अमेजन के घने जंगलों में रहने वाली आवा जनजाति, जिसे 'गुआजा ट्राइब्स' भी कहा जाता है, पूरी तरह जंगलों पर निर्भर जीवन जीती है। यह जनजाति खानाबदोश शिकारी समुदाय मानी जाती है। इनके जीवन की सबसे खास बात वन्यजीवों के साथ उनका गहरा भावनात्मक रिश्ता है। यहां की महिलाएं बंदर, गिलहरी, जंगली सूअर और दूसरे जानवरों के अनाथ बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा बना लेती हैं। वे इन जानवरों की देखभाल उसी तरह करती हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे की करती है। कई बार वे उन्हें अपना दूध पिलाकर बड़ा भी करती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जानवर भी इंसानों के इस प्यार का जवाब बेहद खास तरीके से देते हैं। पालतू बने जानवर जंगलों में ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर फल और औषधीय जड़ी-बूटियां नीचे लाकर आदिवासियों की मदद करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था 'सर्वाइवल इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 500 साल पहले इस जनजाति की आबादी हजारों में थी, लेकिन अब दुनिया में इनके केवल करीब 500 लोग ही बचे हैं। इनमें से भी लगभग 100 लोगों का बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। जंगलों में अवैध कटाई, खनन और भू-माफियाओं के कब्जों के कारण इनके घर और जीवन दोनों खतरे में पड़ गए हैं। इंसान और जानवरों के बीच ऐसा तालमेल आधुनिक समाज के लिए किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता। हालांकि इस जनजाति का अस्तित्व अब गंभीर खतरे में है।

मानसिक स्वास्थ्य संकट

बड़ी चुनौती बना डिप्रेशन और तनाव

हर दिन होती हैं 42 मौतें

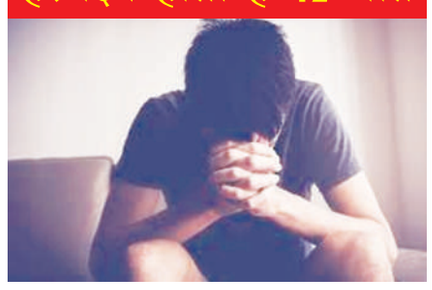

निज संवाददाता : मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य आज भारत के सामने उभरती हुई सबसे बड़ी हेल्थ चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इसका गंभीर संकेत 2024 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान 15,491 लोगों ने आत्महत्या की, यानी औसतन हर दिन 42 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा सिर्फ एक अपराध या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि गहराते मेंटल हेल्थ संकट की ओर भी इशारा करता है। किस तरह मानसिक स्वास्थ्य बन रहा चुनौती? विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों और युवाओं में बढ़ता तनाव इस संकट का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, करियर को लेकर अनिश्चितता और लगातार बढ़ती अपेक्षाएं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश छात्र आत्महत्या के मामलों में देश में तीसरे स्थान पर है और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली छात्र आत्महत्याओं में लगभग 10 फीसदी हिस्सेदारी अकेले इसी राज्य की है। हैरान कर देते हैं लड़कियों के मामले चिंताजनक बात यह है कि छात्राओं पर मानसिक दबाव का असर अधिक दिखाई दे रहा है। वर्ष 2024 में राज्य में 731 छात्राओं और 716 छात्रों ने आत्महत्या की। इसे बढ़ते शैक्षणिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं और भावनात्मक तनाव से जोड़कर देखते हैं। हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या कभी भी अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। इसके पीछे लंबे समय से चल रही मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, चिंता और इमोशनल संघर्ष छिपे हो सकते हैं। इसलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। इसके लक्षण को पहचानें अहमदाबाद स्थित एक निजी मनोचिकित्सा केंद्र की कंसलटेंट और हैप्पीनेस फर्स्ट की एक्सपर्ट डॉ. विधि पटेल वैष्णव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बार-बार मौत या आत्महत्या की बातें करने लगे, अत्यधिक चिंता और बेचैनी महसूस करे, खुद को निरर्थक समझने लगे, अचानक लोगों से दूरी बनाने लगे या अपनी प्रिय चीजें दूसरों को देने लगे, तो इसे गंभीर चेतावनी संकेत माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है। डॉ का कहना है कि समय पर मेडिकल सहायता और इमोशनल सहयोग कई जिंदगियां बचा सकता है। अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना, स्क्रीन टाइम कम करना और जीवन में संतोष की भावना विकसित करना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर दें ध्यान विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाना समय की जरूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट और जागरूकता अभियान इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पांच पोते-पोतियों की दादी बनीं बॉडीबिल्डिंग चैंपियन

72 वर्ष की उम्र में भी शानदार फिटनेस व मजबूत मसल्स की हैं मालकिन

निज संवाददाता : पांच पोते-पोतियों की दादी ताइवान की 72 वर्षीय लिन सुई-त्जु अपनी शानदार फिटनेस, मजबूत मसल्स और आत्मविश्वास भरी मौजूदगी की वजह से दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। लिन सुई-त्जु ताइवान की सबसे उम्रदराज सक्रिय महिला बॉडीबिल्डर्स में गिनी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने 2025 प्रेसिडेंट्स कप बॉडीबिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल कर सभी को हैरान कर दिया। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि फिटनेस और आत्मविश्वास के लिए कोई तय उम्र नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिन ने अपना फिटनेस सफर युवावस्था में नहीं, बल्कि 69 साल की उम्र में शुरू किया। वह पहले डायबिटीज एजुकेटर के रूप में

काम करती थीं और लोगों को स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदे समझाती थीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अधिकतर बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज से दूरी बनाकर रखते हैं, तो उन्होंने खुद उदाहरण बनने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उन्होंने जिम जाना शुरू किया और वेट ट्रेनिंग अपनाई। शुरुआत में उन्हें लगता था कि वजन उठाना केवल बड़े मसल्स बनाने के लिए होता है, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह शरीर को मजबूत बनाने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी बेहतरीन तरीका है। आज उनका फिटनेस रूटीन बेहद अनुशासित है। वह सप्ताह में छह दिन ट्रेनिंग करती हैं, जिसमें वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शामिल होती हैं। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में लिन बॉडीबिल्डिंग स्टेज पर पर्पल बिकिनी में आत्मविश्वास के साथ पोज देती नजर आईं। उन्होंने अपनी ताकत और फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया। लिन का कहना है कि फिटनेस ने उन्हें सिर्फ मजबूत शरीर ही नहीं, बल्कि नया आत्मविश्वास भी दिया है। उनके अनुसार असली खूबसूरती बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के आत्मविश्वास और सम्मान में होती है। जिम के अलावा लिन पेंटिंग, योग और बॉलरूम डांस भी करती हैं।

पूर्ववर्ती सरकार में सामाजिक योजनाओं में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी : शुभेंदु

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार का एक लक्ष्य यह पक्का करना है कि राज्य की अलग-अलग सामाजिक योजनाओं का फ़ायदा सिर्फ़ असली लाभार्थियों तक ही पहुंचे। उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम के रेयापारा में जनकल्याण शिविर का उद्घाटन किया और आम लोगों से सीधे कैंप में आकर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने की अपील की। पिछली तृणमूल सरकार के दौरान अलग-अलग सामाजिक योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कई मामलों में असली लाभार्थियों को इससे वंचित रखा गया, जबकि अयोग्य लोगों को सरकारी फ़ायदे मिले। ₹

उन्होंने कहा-राज्य में 1,100 जगहों पर जनकल्याण शिविर हो रहे हैं। इन कैंपों के ज़रिए 54 ज़रूरी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। पहले सरकारी पैसा योग्य लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता था। मरे हुए लोगों, गैर-भारतीय नागरिकों और यहां तक कि पुरुषों को भी लक्ष्मी भंडार का फ़ायदा मिला है। कुछ जगहों पर पुरुषों को विधवा भत्ता भी दिया गया है। डोमकल के एक ब्लॉक में 3,500 फ़र्ज़ी अकाउंट मिले हैं। मैं जहां भी हाथ लगाता हूं, पिछली सरकार का करप्शन सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट का फायदा पाने के लिए नई जानकारी क्यों इकट्ठा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ट्रांसपेरेंट और सही बेनिफिशियरी लिस्ट बनाना है। उन्होंने कहा-हम नहीं चाहते कि कोई घुसपैठिया या गैर-भारतीय सरकारी स्कीम का फायदा उठाए। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि असली लोगों को सीधे फायदा मिले। किसी भी बिचौलिए के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर लोग सहयोग करेंगे, तो सरकार भी उनके साथ रहेगी।उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर भी रोशनी डाली। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अन्नपूर्णा योजना का पैसा पहले ही 79 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रजिस्टर कराने का मौका मिलेगा। सर्वे या लिस्ट तैयार करने में किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट सरकार के टोल-फ्री नंबर पर करने का सिस्टम भी बनाया गया है।

जसपाल राणा : इतनी जल्दी क्या थी जाने की?

निज संवाददाता : जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी जगत के प्रमुख खिलाड़ियों और कोचों में से एक थे। 12 जून 2026 को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। जसपाल राणा 49 साल के थे। मात्र 49 वर्ष में चले जाना निश्चय ही हृदय विदारक है। देश के लिए अपूरणीय क्षति है। जसपाल निशानेबाजी के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में 15 पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया, स्वयं एशियाई खेलों और ओलपिंक में देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद नई पीढ़ी को तैयार करने में जुट गए। इस समय वे युवा निशानेबाज मनु भाकर के गुरु थे। जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारतीय खेल इतिहास के सबसे चमकदार व होनहार निशानेबाज थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जन्मे जसपाल राणा को उनके पिता नारायण सिंह राणा ने बीएसएफ अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित करवाया था। 12 वर्षीय राणा ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप से राष्ट्रीय निशानेबाजी में पदार्पण किया था। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन यह छोटा बालक इतना करिश्माई निकलेगा।जसपाल ने आरम्भ में पिस्टल और राइफल दोनों से अभ्यास किया किंतु बाद में फेडरेशन ने एक इवेंट के लिए एक ही शूटर को चुनने का नियम लागू किया जिसके बाद उन्होंने पिस्टल शूटिंग को चुना। जसपाल 12 वर्ष की आयु तक आते आते राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे थे। उन्होंने 1988 में 12 वर्ष की अवस्था में ही 31वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया था। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियाई खेलों को मिलाकर कुल 23 पदक अपने नाम किए थे। जसपाल ने एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में नौ स्वर्ण, चार रजत व दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एशियाई चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता जबकि विश्व जूनियर चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जसपाल ने कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में अद्भुत व शानदार प्रदर्शन कर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। 1994 मिलान विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में उनकी जीत यादगार रही। उन्होंने यह जीत दर्द से कराहते हुए प्राप्त की थी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले उन्हें घुटने में फोड़ा हो गया था और डॉक्टरो ने उन्हें सर्जरी की सलाह देकर अस्पताल से छुट्टी देने से मनाकर दिया था किंतु उन्होंने राष्ट्रप्रथम की भावना को ध्यान में रखा और डॉक्टरों की सलाह को दरकिनार करते हुए प्रतियोगिता मे भाग लेने का निश्चय किया किंतु अस्पताल से निकलने के बाद उसी रात फोड़ा फूट गया और उनका दर्द बढ़ गया। वे अपनी जींस तक नहीं उतार पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जीन्स को फाड़कर ही हाफ पैंट बनाई और उसे पहनकर ही अगली सुबह प्रतियोगिता में उतरे। राणा ने असहनीय दर्द में मैच खेला और जूनियर कैटेगरी में विश्व रिकार्ड के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ष उन्होंने हिरोशिमा एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। 1994 में हिरोशिमा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जसपाल को इसी वर्ष मात्र 18 वर्ष की अवस्था में अर्जुन पुरस्कार मिला। जसपाल राणा का जीवन खेल व राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। वह हर बार रेंज पर उतरते समय देश का गौरव अपने साथ लेकर चलते थे। एक खिलाड़ी के रूप में तो उनका कैरियर शानदार रहा। दूसरी पारी में वह एक अच्छे प्रशिक्षक बने। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीते। उन्होंने सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला और चिंकी यादव सहित कई अन्य निशानेबाज़ो के कैरियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई ।जसपाल राणा की उपलब्धियों ने देश को खुशी से झुमने का अवसर दिया। अगली पीढ़ी को गढ़ा। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के लोकप्रिय गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने जसपाल के नाम से वर्ष 1999 में एक गीत बनाया था। मात्र 49 वर्ष की अवस्था में जसपाल का जाना एक शून्य उत्पन्न कर गया है।

वफादारी के चोले में टीएमसी नेताओं की सियासी मजबूरी

निज संवाददाता : राजनीति में वफादारी और मजबूरी के बीच की लकीर अक्सर इतनी पतली होती है कि आम आदमी तो क्या, खुद नेता भी भूल जाते हैं कि वे किस तरफ खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और बाबुल सुप्रियो की कहानी इसी सच्चाई की एक जीती-जागती मिसाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार के बाद जब पार्टी के करीब बीस सांसद बगावत पर उतर आए और मोदी सरकार के साथ खड़े होने का एलान कर दिया, तब यही तीनों नेता दीदी यानी ममता बनर्जी की वफादारी का ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया कि वे ममता जी के साथ हैं और हमेशा टीएमसी में ही रहेंगे। कीर्ति आजाद ने भी संकट की इस घड़ी में ममता बनर्जी का हाथ थामे रखने का एलान किया। लेकिन जो बात इन बयानों के पीछे छिपी है, वह यह है कि इन नेताओं के पास फिलहाल कोई और चारा है भी नहीं। सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाकर भाजपा छोड़ी थी, लेकिन भाजपा में आज भी उनके कई पुराने मित्र मौजूद हैं। यही कारण है कि जब टीएमसी में तूफान आया तो उनकी चुप्पी ने सबको चौंकाया। वे न बागी खेमे में नजर आए, न ममता के साथ खुलकर। लेकिन जब यह साफ हो गया कि भाजपा उनके लिए अपने दरवाजे खोलने के मूड में नहीं है, तो उनकी कथित वफादारी की घोषणा सामने आ गई।बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक भाजपा के चमकते सितारे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन धीरे-धीरे पार्टी में उनकी पूछ कम होती गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा ने नई करवट ली तो पुरानी पीढ़ी के कई नेताओं को हाशिये पर धकेल दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में घुट-घुटकर रहते रहे और अंदर ही अंदर असंतोष पकता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर भटकाव का शिकार रहा और अंततः वे तृणमूल कांग्रेस में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से करीब साठ हजार वोटों से जीते। लेकिन यह जीत उनकी अपनी नहीं, ममता बनर्जी की लहर थी। अब जब वही लहर उतर रही है, तो उनके पास लौटने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। कीर्ति आजाद की कहानी तो और भी दिलचस्प है। दिसंबर 2015 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुले तौर पर निशाना बनाने के लिए उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। वे 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में धनबाद से टिकट दिया, लेकिन वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2024 में वे तृणमूल कांग्रेस के जरिये बर्धमान-दुर्गापुर से लोकसभा पहुंचे। कीर्ति आजाद इस सीट से करीब 14 हजार वोटों से जीते। इस तरह एक ऐसे नेता जो कभी भाजपा के दिग्गज क्रिकेटर-सांसद हुआ करते थे, उनकी राजनीतिक यात्रा भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस से टीएमसी तक आ पहुंची। अब भाजपा उनसे दूरी बनाए हुए है और कांग्रेस भी उन्हें वापस लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मजबूरी यही है कि ममता की डूबती नैया को थामे रखो और उसे वफादारी का नाम दो।बाबुल सुप्रियो की कहानी इन दोनों से थोड़ी अलग लेकिन उसी धागे में पिरोई हुई है। वे आसनसोल से दो बार सांसद रहे और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री भी रहे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा को बंगाल में करारी हार मिली और पार्टी के भीतर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, तो बाबुल सुप्रियो ने भी भाजपा से मुंह मोड़ लिया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी में शामिल होने वाले नेताओं में शामिल थे। तृणमूल ने उन्हें बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में उतारा और वे जीत भी गए। लेकिन विधायक बनने के बाद भी उनकी राजनीतिक हैसियत वही नहीं रही जो कभी केंद्रीय मंत्री के रूप में थी। अब जब टीएमसी खुद संकट में है, तो भाजपा की ओर उनकी नजर स्वाभाविक रूप से जाती है, लेकिन भाजपा उन्हें पार्टी में वापस लेने की कोई इच्छा नहीं रखती। उधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा और भयंकर 'युद्ध' छिड़ा हुआ है। टीएमसी के बीस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपा है जिसमें अलग गुट बनाने की सूचना देते हुए लोकसभा में अलग बैठने की जगह देने की मांग की गई है। दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए लोकसभा में कम से कम उन्नीस सांसदों का समर्थन आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि टीएमसी सांसदों का समर्थन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलता है, तो सरकार के लिए परिसीमन और एक देश-एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है। बागी गुट अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार सांसदों का समर्थन जुटा रहा है।इस पूरे घटनाक्रम में यह तीन नेता एक अजीब कशमकश में फंसे हुए हैं। एक तरफ बागी खेमा है जो भाजपा का दामन थामने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का खेमा है। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और बाबुल सुप्रियो न उस पार जा सकते हैं, न इस पार रह सकते हैं। बागी खेमे के साथ जाने का मतलब होगा भाजपा के दरवाजे पर दस्तक देना, लेकिन भाजपा उनके लिए वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ममता के साथ बने रहना इनकी मजबूरी है, लेकिन यह तीनों इसे वफादारी का नाम देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बहरहाल, उक्त तीन के अलावा तृणमूल कांग्रेस में और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। महुआ मोइत्रा, सौगात रॉय, और सायोनी घोष जैसे नाम टीएमसी के उन चेहरों में शामिल हैं जो भाजपा के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। महुआ मोइत्रा का राजनीतिक और वैचारिक रुख भाजपा के एकदम विपरीत रहा है और वे लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहती हैं। सौगात रॉय वामपंथी झुकाव वाले वरिष्ठ नेता हैं जिनका भाजपा से कोई तालमेल कभी नहीं बैठा। इनके अलावा वे टीएमसी विधायक और नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके लिए भी भाजपा की जगह तंग है। गौरतलब हो, राजनीति का यह खेल बड़ा निर्मम होता है। जब तक हवा अनुकूल रहती है, तब तक दावेदारी होती है। जब हवा पलट जाती है, तब मजबूरियां सामने आती हैं और उन्हें सिद्धांत का जामा पहना दिया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और बाबुल सुप्रियो तीनों ने अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा को छोड़ा। तीनों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। आज वे ममता बनर्जी की वफादारी की बात करते हैं, लेकिन असल में यह वफादारी नहीं, एक सियासी मजबूरी है जिसने वफादारी का चोला ओढ़ लिया है। जो नेता घुट-घुटकर पार्टी में बने रहते हैं और मन मसोसकर बयानबाजी करते हैं, वे वफादार नहीं, मजबूर होते हैं।

मनोरंजन

सुमन कल्याणपुर: तीन दशकों तक जिन्हें ये मानकर सुना गया कि गा रही हैं लता

निज संवाददाता : जानी-मानी गायिका सुमन कल्याणपुर का बीते 31 मई को मुंबई में 89 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बहुत शांति से दुनिया को अलविदा कहा। सुमन की आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर की आवाज से होती थी। फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 11 भाषाओं में 3000 से ज्यादा फिल्मी-नॉन फिल्मी गाने गाए। 60 और 70 के दशक में बनाई थी खास पहचान सुमन कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से संगीत जगत में एक खास पहचान बनाई थी। उस दौर में लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के रहते हुए भी उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। उनके गाए 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे', 'ना ना करते प्यार तुम्हीं से' और 'तुमने पुकारा और हम चले आए' जैसे गाने आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, असमी, कन्नड़, बंगाली और ओडिया समेत कई भाषाओं में गाने गाए।हालांकि लोग अक्सर उनकी आवाज की तुलना लता मंगेशकर से करते थे, लेकिन सुमन हमेशा इस तुलना को खारिज करती थीं। साल 2022 के एक इंटरव्यू में उन्होंने लता को अपना बेहद करीबी दोस्त बताते हुए कहा था कि उनसे मिलना हमेशा एक सहेली से मिलने जैसा एहसास कराता था। लता मंगेशकर से हुबहू मिलती थी आवाजसुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी। दोनों के गाने का अंदाज और सुरों पर पकड़ एक जैसी मानी जाती थी। कई बार लोग उनकी और लता की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे।इसी खूबी की वजह से जब 1960 के दशक में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच विवाद हुआ तो सुमन कल्याणपुर संगीतकारों की पसंद बनीं और उन्होंने रफी साहब के साथ एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने गाए। इस पर बात करते हुए सुमन कल्याणपुर ने एक इंटरव्यू में कहा-मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। कॉलेज के दिनों में मैं उनके गाने सुनती थी। मेरी आवाज पतली और नाजुक थी, मैं क्या कर सकती थी। शुरुआत में रेडियो सेलोन, मेरे गानों को बिना नाम के चलाते थे, जिससे लोगों को ज्यादा भ्रम होता था। कभी-कभी मेरे रिकॉर्ड्स में नाम भी गलत लिखा होता था। एक समय जब एचएमवी ने 50 बेस्ट गानों की रिकॉर्डिंग जारी की, तो उसमें सबसे ज्यादा गाने सुमन के डाले गए। जबकि कैसेट के कवर में सिर्फ मोहम्मद रफी, तलत महमूद और किशोर कुमार की तस्वीर लगाई गई थी। दावाः ऐ मेरे वतन के लोगों गाने की पहली पसंद थीं सुमन, आखिरी वक्त में छीना गयासालों पहले नांदेड़ में आयोजित आषाढी महोत्सव के दौरान सुमन कल्याणपुर ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मशहूर गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, उनके लिए लिखा गया था। वो ये गाना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाने वाली थीं। उन्होंने गाने की प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन परफॉर्मेंस से ठीक पहले, वो गाना लता मंगेशकर को दे दिया गया। इंटरव्यू में सुमन ने कहा था, जब मैं कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि मैं इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाऊं। ऐ मेरे वतन लोगों मुझसे छीन लिया गया था यह मेरे लिए बड़ा सदमा था। वह बात आज भी चूभती है। जाने-माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन से एक इंटरव्यू के लिए समय मांगते रहे, लेकिन सुमन हर बार टाल जाती थीं। आखिर 45 साल के बाद अमीन सयानी का इंतजार 2005 में खत्म हुआ, जब सुमन एक घंटे के इंटरव्यू के लिए राजी हुईं। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू की मंजूरी सिर्फ इस शर्त पर दी कि कोई उनकी फोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई सवाल उन्हें असहज लगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी।सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वे पेंटर बनना चाहती थीं, लेकिन सुमन की आवाज को उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले ने परख लिया था। उन्होंने सुमन के पिता से संगीत सिखाने की बात कही।पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रहीं थीं, लेकिन समय के साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी और वो गंभीरता से सीखने लगीं। सुमन ने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखीं।

बक्सा टाइगर रिजर्व : फिर सुनाई देगी बाघों की दहाड़

निज संवाददाता : बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई दे सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 29 जुलाई यानी ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर रिजर्व में दो मादा बाघों को छोड़ा जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, इन बाघों को मानस टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर से लाने पर विचार चल रहा है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ के सदस्य सौमित्र दासगुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दो मादा बाघों के साथ शुरू की जा सकती है और उन्हें 29 जुलाई को बक्सा में लाने की योजना है। वहीं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एमटीसीए) के सदस्य सचिव संजय कुमार कि हमने बक्सा में बाघों को छोड़ने के लिए 29 जुलाई का टारगेट रखा है। बिहार के वाल्मीकि के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य रिजर्व जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क पर भी विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि का पारिस्थितिक तंत्र बक्सा के जंगलों से काफी मिलता-जुलता है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24 मई को बक्सा में बाघों के पुनर्वास की योजना की घोषणा की थी।बता दें कि बंगाल के बक्सा टाइग रिजर्व में स्थायी बाघ आबादी की कमी को देखते हुए 2016-17 में टाइगर ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों के लिए बेहतर आवास तैयार करना, शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाना और जंगलों के भीतर बसे गांवों का पुनर्वास करना है। अब तक भूटिया बस्ती और गंगुटिया गांवों को स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि जयंती गांव के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, 400 से अधिक परिवारों में से 97 फीसदी ने पुनर्वास के लिए सहमति जताई है। वन विभाग का मानना है कि इससे बाघों के लिए सुरक्षित और निर्बाध क्षेत्र उपलब्ध होगा।वहीं, 2021 के बाद से कैमरा ट्रैप में बक्सा में कई बार बाघों की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे उम्मीदें बढ़ी हैं। अधिकारियों के अनुसार, मानस टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि से बाघ लाने पर विचार हो रहा है। वाल्मीकि में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2023 में 50 से अधिक हो गई है और अब यह अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त बाघों को कम आबादी वाले रिजर्व में भेजना वन्यजीव प्रबंधन का अहम हिस्सा है। पूर्व मुख्य वन्यजीव संरक्षक प्रदीप व्यास ने पहले कहा था कि 2026 तक हर तीन साल में दो बाघ बक्सा लाने की योजना है।

'तेजाब में मोहिनी के चरित्र के लिए माधुरी ही थी पहली व आखिरी पसंद'

निज संवाददाता : बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के कॅरियर को नई दिशा देने वाली फिल्म तेजाब के निर्माता-निर्देशक एन. चंद्रा ने वर्षों बाद एक राज पर से पर्दा उठाया है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि फिल्म तेजाब में माधुरी के निभाए गए मोहिनी के आइकॉनिक किरदार के लिए माधुरी का चयन किस प्रकार हुआ था और इसके पीछे निर्देशक की क्या सोच थी। निर्माता एन चंद्रा ने हाल ही में एक डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के एक विशेष एपिसोड में उस समय की यादें साझा करते हुए बताया कि आखिर क्यों माधुरी ही उनकी पहली और एकमात्र पसंद थीं। एन. चंद्रा ने बताया, जब मैंने पहली बार माधुरी दीक्षित को देखा था, तभी मुझे यह महसूस हो गया था कि इस लड़की में कुछ तो बेहद खास बात है, जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। उस दौर में, एन. चंद्रा एक फिल्म एडिटर के तौर पर कई परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। इसी सिलसिले में उन्हें एक फिल्म बजरंगी के सेट पर जाने का अवसर मिला, जहां उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। माधुरी उस समय अपने करियर के शुरुआती चरण में थीं और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। निर्देशक ने कहा-उस पहली मुलाकात में ही मुझे यह गहरा एहसास हुआ कि उनमें एक असाधारण प्रतिभा छिपी है।शायद उसी पल मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि भविष्य में यदि कभी मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से माधुरी के साथ काम करना चाहूंगा। निर्देशक एन. चंद्रा ने आगे बताया कि जब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना तेजाब की कहानी पर काम शुरू किया और मोहिनी के जटिल एवं सशक्त किरदार की परिकल्पना की, तब उनके मस्तिष्क में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, और वह नाम था माधुरी दीक्षित। उन्होंने दृढ़ता से कहा, इस भूमिका के लिए मेरी पहली पसंद भी माधुरी थीं और मेरी आखिरी पसंद भी वही थीं। मैंने किसी अन्य अभिनेत्री के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि इस किरदार को केवल वही सबसे बेहतर और प्रभावी तरीके से पर्दे पर उतार सकती हैं। उन्होंने माधुरी की नृत्य क्षमता और भावपूर्ण अभिनय को पहले ही भांप लिया था।एन. चंद्रा ने एक दिलचस्प पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कई बार किस्मत भी किसी परियोजना की सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है। उस समय फिल्म के नायक अनिल कपूर के सेक्रेटरी राकेश नाथ ही माधुरी दीक्षित के भी सेक्रेटरी का काम संभाल रहे थे।

इस संयोग के कारण दोनों प्रमुख कलाकारों की तारीखों का समायोजन करना और अन्य जरूरी बातें तय करना बेहद आसान हो गया। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा-अगर किस्मत साथ दे, तो कई मुश्किल लगने वाले काम भी असाधारण सरलता से पूरे हो जाते हैं। 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई तेजाब उस दौर की सबसे बड़ी व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया, और मोहिनी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

पद्मश्री सुदर्शन को रूस में मिला 'ग्रैंड सैंड मास्टर कप'

यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय कलाकार

निज संवाददाता : ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को रूस में आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में प्रतिष्ठित 'रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026' से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। यह सम्मान उन्हें रेत कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और ग्लोबल वार्मिंग विषय पर बनाई गई प्रभावशाली रेत की मूर्ति के लिए प्रदान किया गया। 11 जून 2026 से शुरू हुए इस अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में विभिन्न देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। महोत्सव की विशेष जूरी समिति ने सर्वसम्मति से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के नाम का चयन किया। उनकी कलाकृति ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया, जिसकी व्यापक सराहना की गई। पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अपनी रेत कला के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय कला जगत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय** : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय** : 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता**, मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)